

[2023] 7 एस. सी. आर. 530

एम/एस। डी. एन. सिंह

बी.

आय कर आयुक्त, केंद्रीय, पटना और

एक और

(सिविल अपील सं. 3738-3739 2023 का)

16 मई, 2023

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961। 69 ए-का दायरा और प्रयोज्यता -

एस. 69 अस्पष्टीकृत धन, सराफा, आभूषण या अन्य के साथ सौदा

कब

प्रावधान का प्रभाव माना जाता है

बहुमूल्य वस्तुएँ

-

लागू-एस में 'मालिक' शब्द की सीमा। 69 ए-आयोजित (प्रति के. एम.)

जोसेफ, जे.): एस लागू करने के लिए। 69 अधिनियम का ए, यह अपरिहार्य है कि

अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि दूसरी मूल्यवान वस्तु के मालिक

निर्धारिती एक बेली जो एक सामान्य वाहक है, इसका मालिक नहीं है।

माल-एक बेली जो एक सामान्य वाहक है, उसे आवश्यक रूप से माल का कब्जा सौंपा जाएगा-जमानत का उद्देश्य

सामान की डिलीवरी आम वाहक द्वारा माल प्राप्तकर्ता को की जाती है या प्रेषक के निर्देशों के अनुसार-निर्वाह के दौरान

माल की दुलाई के अनुबंध का, बेली नहीं बनेगा

माल का मालिक-वाहक को सौंपने के मामले में

माल की बिक्री के अनुबंध के अलावा, कब्जा

वाहक इसे माल के मालिक में परिवर्तित नहीं करेगा

एक मालिक के पूर्ण अधिकारों में आनंद की शक्ति शामिल है जो

इसके अलावा नष्ट करने की शक्ति शामिल है; अधिकार का अधिकार जिसमें आगे दूसरों को बाहर करने का अधिकार शामिल है; अंतर विवोस को अलग करने या प्रतिभूति के रूप में चार्ज करने की शक्ति और वसीयत करने की शक्ति

संपत्ति-एक वाहक के पास इनमें से कोई भी अधिकार या शक्तियां नहीं होती हैं-एक वाहक द्वारा बिक्री का अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक कि उसे आचरण द्वारा प्रतिरक्षित नहीं किया जाता है।

उस माल के मालिक से जो बदले में मालिक को अलग कर देगा

खरीदार के शीर्षक पर आक्षेप-आयोजित (प्रति हृषिकेश रॉय, जे।) (सहमत): s.69A प्रमाण के एक नियम के रूप में प्रदान करता है कि

लागू करने के लिए प्रभाव-निर्धारिती को धन का स्वामी होना चाहिए,

सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ जिन पर वह काम नहीं कर सकता है।

एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के लिए-स्वामित्व का निर्धारण करना

कर देयता को लागू करने के लिए माल एक महत्वपूर्ण कारक है-किसी के पास

केवल अधिकार और माल पर कानूनी स्वामित्व या अधिकार के बिना

530 एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त

एस के दायरे में नहीं आएगा। 69 ए-एक निर्धारिती कर सकता है फिर भी माना जाने वाला मालिक माना जाता है यदि अधिकार है

निर्धारिती पर आरोप लगाया जाता है और इससे बेहतर दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति निर्धारिती के दावे का विरोध नहीं कर रहा है-वर्तमान मामले में, निर्धारिती निश्चित रूप से बिटुमेन का मालिक नहीं था-बल्कि वह वाहक था जो प्रेषक से माल की आपूर्ति कर रहा था-तेल विपणन कंपनियां प्रेषक को-सड़क निर्माण विभाग विशेष रूप से, माल की कम डिलीवरी के कारण, निर्धारिती का कब्जा गैरकानूनी था-इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि

एस के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती मालिक नहीं है। 69 ए-अनुबंध अधिनियम, 1872-एसएस। 148 , 151 - माल बिक्री अधिनियम, 1930-एस. एस. 39 , 27 .

आय कर अधिनियम, 1961 - s.69A-'s' के अर्थ में 'अन्य मूल्यवान लेख'। 69 ए-क्या यह आंतरिक रूप से महंगा होना चाहिए-क्या

बिटुमेन-कच्चे तेल के प्रसंस्करण के दौरान अवशिष्ट ऑफशूट सामग्री, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, विमानन ईंधन आदि जैसे इसके मूल्यवान घटकों को छोड़कर, 'एस' के अर्थ में धन, सर्राफा और आभूषणों के साथ 'अन्य मूल्यवान वस्तु' की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। 69 ए-आयोजित (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.): बिटुमेन कम मात्रा में या बड़ी मात्रा में पाया जा सकता है-यदि 'वस्तु' को 'मूल्यवान' पाया जाना है, तो कम मात्रा में इसका केवल कुछ मूल्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक अच्छी कीमत के लायक होना चाहिए 'या' एक बड़े सौदे के लायक होना चाहिए 'और यह नहीं कि इसका' मूल्य 'है - s.69A तब 'बिटुमेन' से आकर्षित होगा क्योंकि इसे 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है-आयोजित (ऋषिकेश राय, जे. के अनुसार) (सहमति): जब एजुस्टेड जेनरिस का सिद्धांत लागू किया जाता है, तो पूर्ववर्ती शब्द एस में होते हैं। 69 जैसे पैसा,

सर्राफा, आभूषण से पता चलता है कि 'अन्य मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश जो उन शब्दों का अनुसरण करता है, केवल उच्च मूल्य की वस्तुओं को शामिल करने को उचित ठहराएगा-'अन्य' वाक्यांश को पढ़ने का कोई अन्य तरीका। विशिष्ट प्रकार की उपेक्षा करके मूल्यवान लेख 'या' मूल्यवान लेख '

एस के पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित माल। 69 ए, गलत होगा और प्रावधान की सादे भाषा के साथ हिंसा करेगा और विधायी उद्देश्य से परे यात्रा करेंगे-इसके अतिरिक्त, उक्ति 'नोसिटुर ए सोसाइटिस' यानी (एक शब्द अपने सहयोगियों द्वारा जाना जाता है) भी उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि अन्य मूल्यवान वस्तुओं को होना चाहिए

चांदी की छड़ें, या आभूषण या धन की प्रकृति की वस्तुएँ अर्थात् केवल

उच्च मूल्य की वस्तु-यह दिया गया है कि कोई भी कानून संभवतः उन सभी मूल्यवान वस्तुओं की एक विस्तृत सूची प्रदान नहीं कर सकता है जो उच्च आय निर्धारिती को अपनी आय को समायोजित करने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं-केवल मूल्यवान [2023] 7 एस. सी. आर. की एक सांकेतिक सूची।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेखों का व्यावहारिक रूप से खंड में उल्लेख किया जा सकता है-लेकिन 'अन्य मूल्यवान लेख' की अभिव्यक्ति में बिटुमेन को शामिल करना। 69 ए, बेतुकेपन में परिणाम देगा, जिसे किसी को छोड़ने की आवश्यकता है-किराना स्टोर और बिटुमेन से सामान्य स्थान की वस्तुएं आंतरिक रूप से भिन्न हैं

एस में उच्च मूल्य की वस्तुएँ। 69 ए और एक व्याख्यात्मक अभ्यास के माध्यम से, किसी को उन्हें सोने की छड़ और आभूषण जैसी वस्तुओं के साथ वर्गीकृत नहीं करना चाहिए।

आय कर अधिनियम, 1961 - s.69A-क्या कोई चोर पकड़े गए सामान का मालिक हो सकता है (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.): की अवैधता

स्वामित्व एस की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकता है। 69 ए कि मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारिती को वस्तु का मालिक ढूंढना चाहिए, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व या संपत्ति का पता लगाए बिना। जब यह स्पष्ट होता है कि कोई और मालिक है, तो एक व्यक्ति पाया जाता है

कब्जा, जो अवैध है, एस के तहत मालिक पाया जा सकता है। 69 ए-यह कानून को औचित्य से परे तनाव देना होगा यदि न्यायालय को एस के अर्थ के भीतर एक चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता देनी थी। 69 ए-एक चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में पहचानने का मतलब यह भी होगा कि संपत्ति के मालिक को मालिक के रूप में पहचाना जाना बंद हो जाएगा, जो वास्तव में सबसे चौंका देने वाला परिणाम होगा-जबकि किसी व्यक्ति का कब्जा हो सकता है।

उचित मामलों में, जब उसके कब्जे के स्रोत और गुणवत्ता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो एक मूल्यांकन अधिकारी को उसे मालिक पाते हुए उचित ठहराएं, जब तथ्यों का पता चलता है कि वाहक मालिक नहीं है और कोई और मालिक है, तो उसे मालिक के रूप में वर्णित करने से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो अन्यायपूर्ण होने के अलावा सबसे अधिक अवैध हैं।

आय कर अधिनियम, 1961 - s.69A-लेख और मूल्यवान लेख विशिष्ट-आयोजित (ऋषिकेश राय, जे. के अनुसार): मूल्य की वस्तुएँ एक ऐसी प्रजाति हैं जिसमें मूल्यवान वस्तुएँ एक प्रजाति होती हैं अर्थात् उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का एक उपसमुच्चय-मूल्य वाली वस्तु एक मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती है-सभी विविध वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करने से एक ऐसी व्याख्या होगी जो कानून के उद्देश्य और विधानमंडल के इरादे के लिए विदेशी होगी। 69 ए चिंतित है।

सिद्धांत/सिद्धांत-एक समाज और सामान्य न्याय -

चर्चा की।

मैक्सिमस-एब्सोलुटा सेंटेंशिया एक्सपोज़िटोर नॉन इंडिजेट-एक्सप्लेनड।

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़ना: (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.):

1. जब माल को एक सामान्य वाहक को सौंपा जाता है, तो सौंपना जमानत के अनुबंध के बराबर होगा।

3. माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 39 विक्रेता द्वारा वाहक को बिक्री के अनुबंध के अनुसार वितरण पर विचार करती है। प्रथम दृष्टया खरीदार को माल की डिलीवरी मानी जाएगी। यह वाहक के खरीदार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करे और माल को प्रेषक को या उसके निर्देशों के अनुसार वितरित करे। एक वाहक द्वारा बिक्री [2023] 7 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकार पारित करें सिवाय तब जब इसे माल के मालिक के आचरण द्वारा प्रतिरक्षित किया जाता है जो बदले में मालिक को खरीदार के अधिकार को छीनने से रोकता है। [पारस 42 और 43] [558-एफ-जी; 559-डी]

4. एक व्यक्ति के पास निषिद्ध या निषिद्ध वस्तुएँ हो सकती हैं और

फिर भी धारा 69 ए के दायरे में रहें। दूसरे शब्दों में, स्वामित्व की अवैधता धारा 69 ए की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकती है कि मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारिती को वस्तु का मालिक ढूँढना चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व पाए बिना या जब यह स्पष्ट हो कि कोई और मालिक है, तो कब्जे में पाया गया व्यक्ति, जो अवैध है, धारा 69 ए के तहत मालिक पाया जा सकता है। यह सवाल स्पष्ट रूप से उठेगा कि कब एक सामान्य वाहक खेप देने से इनकार करता है और इसके विपरीत इसे अपने पास रखता है।

चोरी करके उसे मालिक होने का दावा करते हुए बेच देता है। क्या चोर मालिक बन सकता है? यदि न्यायालय धारा 69 ए के अर्थ के भीतर किसी चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता देता है तो यह कानून को औचित्य से परे तनाव देना होगा। चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में पहचानने का मतलब यह भी होगा कि संपत्ति का मालिक संपत्ति को मालिक के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया जाएगा, जो वास्तव में सबसे चौंका देने वाला परिणाम होगा। जबकि किसी व्यक्ति का कब्जा उचित मामलों में हो सकता है, जब कोई स्पष्टीकरण न हो।

उसके कब्जे के स्रोत और गुणवत्ता के बारे में बताते हुए, एक मूल्यांकन अधिकारी को उसे मालिक पाते हुए, जब तथ्यों का पता चलता है कि वाहक मालिक नहीं है और कोई और मालिक है, तो उसे मालिक के रूप में वर्णित करने के लिए ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो अन्यायपूर्ण होने के अलावा सबसे अधिक अवैध हैं। [पैरा 47] [560-जी; 561-ए-डी]

5. आयकर के अतिरिक्त आयुक्त, बिहार बनाम में निर्धारित मालिक के पूर्ण अधिकार। एम/एस। सहाय प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी (पी) लिमिटेड को फिर से दोहराया जा सकता है: (1) आनंद की शक्ति जिसमें नष्ट करने की शक्ति शामिल है। (2) कब्जा करने का अधिकार जिसमें दूसरों को बाहर करने का अधिकार शामिल है। (3) इंटर विवोस को अलग करने या सुरक्षा के रूप में चार्ज करने की शक्ति। (4) संपत्ति को वसीयत करने की शक्ति। एक वाहक के पास इनमें से कोई भी अधिकार या शक्तियाँ नहीं होती हैं। यह सच हो सकता है कि मालिक होने के लिए, सभी एम/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त

मालिक के अधिकार और शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। यह सच हो सकता है कि स्वामित्व कब्जे में रहने के बेहतर अधिकार से जुड़ा हो सकता है और किसी दिए गए मामले में वास्तविक कब्जे को स्वामित्व के साथ सुसंगत किया जा सकता है। कब्जा होने के अधिकार के साथ कब्जे में होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मालिक मालिक है, जब तक कि इसके विपरीत संकेत न हों। लाभकारी बनियान संदर्भ में मालिक के रूप में शीर्षक वाले व्यक्ति को पहन सकता है। एक अन्य अवधारणा जो सामने आती है वह है धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसका संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण होता है और किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे के दावे को विफल करने का बेहतर अधिकार नहीं होता है।

इस निष्कर्ष के द्वारा कि वह धारा 69 ए के अर्थ के भीतर मालिक है। संपत्ति के वास्तविक भौतिक नियंत्रण में एक व्यक्ति और अपने स्वयं के उपयोग के लिए पूरी आय का एहसास स्वामित्व की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। हस्तांतरण को पूरा करने के लिए आवश्यक परिवहन की अनुपस्थिति किसी व्यक्ति को मालिक पाए जाने से विचलित नहीं कर सकती है। तर्क की आत्मा प्रतीत होती है

'उसके अधिकार में' संपत्ति से आय प्राप्त करने की पात्रता। [पारस 58 और 59] [579-बी-जी]

6. एक वाहक के रूप में अपीलार्थी को माल सौंपा गया था। अपीलार्थी का अधिकार बेली के रूप में शुरू हुआ। अदालत आगे बढ़ती है

जिसमें किसी वाहक को सौंपे गए माल का दुरुपयोग या बेईमानी से वाहक के उपयोग में परिवर्तित किया जाना शामिल है। धारा 406 के तहत एक विशिष्ट चित्रण यह स्पष्ट करता है कि एक वाहक द्वारा ऐसा कार्य धारा 406 के तहत अपराध को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को यह पता लगाने की प्रक्रिया में कि अपीलार्थी माल का मालिक है, अपीलार्थी द्वारा अपराध करने की अनुमति देनी होगी। दूसरे शब्दों में, [2023] 7 एस. सी. आर. पर आगे बढ़ना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवार्य रूप से, न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि यह कार्य केवल एक चूक या गलती नहीं थी, बल्कि धारा 406 के तहत अपराध करने में इसे शामिल करने वाले वाहक द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य था। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह पता लगाना चाहिए कि अपीलार्थी ने यह इस राज्य में है कि निर्धारण अधिकारी को यह पता लगाना होगा कि अपीलार्थी को माल को कम समय में पहुँचाने और माल के कब्जे को जारी रखने के जानबूझकर कार्य द्वारा न केवल अनुबंध के विपरीत, बल्कि भूमि के कानून के विपरीत, वाहक अधिनियम 1865 में और दंडात्मक कानून को भी तोड़ते हुए, अपीलार्थी को मालिक के रूप में माना जाना चाहिए। [पैरा 60] [579-एच; 580-ए-ई]

7. बिटुमेन कम या बड़ी मात्रा में पाया जा सकता है।

मात्राएँ। यदि 'वस्तु' को 'मूल्यवान' पाया जाना है, तो कम मात्रा में इसका केवल कुछ मूल्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह 'मूल्यवान' भी होना चाहिए।

अच्छी कीमत 'या' बहुत पैसे के लायक 'और यह नहीं कि इसका' मूल्य 'है। धारा 69 ए तब आकर्षित होगी। लेकिन अगर इसे 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में माना जाए, तो इसके लिए बड़ी मात्रा में स्वामित्व की आवश्यकता होती है।

इस अर्थ में कि बड़ी मात्रा में मूल्य को गुणा करने से, एक 'अच्छी कीमत' या 'बड़ी राशि' प्राप्त होती है, तो यह मूल्यवान वस्तु नहीं होगी। यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि 'बिटुमेन' को 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 79] [590-डी-ई]

आयकर, सलेम बनाम। के. चिन्नाथम्बन (2007) 7 एस. सी. सी. 390 [2007] 8 एस. सी. आर. 496; पटेल रोडवेज लिमिटेड बनाम। बिड़ला यामाहा लिमिटेड (2000) 4 एस. सी. सी. 91: [2000] 2 एससीआर 665; नाथ ब्रदर्स। एक्जिम इंटरनेशनल लिमिटेड v. सर्वश्रेष्ठ सड़क मार्ग लिमिटेड (2000) 4 एस. सी. सी. 553: [2000] 2 एससीआर 538; आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पटियाला (1971) 3 एस. सी. सी. 369 [1972] 1 एस. सी. आर. 639; स्वर्गीय नवाब

सर मीर उस्मान अली खान बनाम। धन कर आयुक्त, 1/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त केंद्र, पटना और अन्य

हैदराबाद (1986) पूरका एससीसी 700 [1986] 3

एस. सी. आर. 1072; आयकर आयुक्त, बॉम्बे और अन्य। वी. पोद्दार सीमेंट प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (1997) 5 एससीसी 482 [1997] 1 पूरका एससीआर 394; अतिरिक्त मैसूर

मिनरल्स लिमिटेड एम. जी. रोड, बेंगलोर बनाम आयकर आयुक्त, कर्नाटक, बेंगलोर (1999) 7 एस. सी. सी. 106 [1999] 2 पूरका एस. सी. आर. 182; औद्योगिक ऋण और विकास सिंडिकेट लिमिटेड v. आयकर आयुक्त, मैसूर और अन्न। (2013) 3 एससीसी 541: [2013] 3 एस. सी. आर. 1082; आयकर आयुक्त, कोलकाता बनाम। एस. एम. आई. एफ. एस. प्रतिभूति लिमिटेड (2012) 13 एस. सी. सी. 488 और रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम। केंद्रीय कलेक्टर

आबकारी, बड़ौदा (1990) 3 एस. सी. सी. 447: [1990] 2 एससीआर 797

(मध्य), बॉम्बे (1982) 138 आई. टी. आर. 570; आयकर आयुक्त बनाम। अमृत लाल चुनिलाल (1984) 40 सी. टी. आर. बॉम्बे 387। आय कर आयुक्त v. एस. पिचार्डमनिकन चेट्टियार (1984) खंड 147 आई. टी. आर. 251; मोहन बी. समतानी बनाम। आय आयुक्त-कर (1993) खंड 199 आई. टी. आर. 370; जे. एस. पारकर बनाम वी. बी. पालेकर (1974) 94 आई. टी. आर. 616 (बम एच. सी.); मोहन बी. समतानी बनाम आय आयुक्त-कर 1993 खंड। 199 आई. टी. आर. 370 कलकत्ता; आयकर आयुक्त बनाम के. आई. पावन्नी (1998) 232 आई. टी. आर. 837; एडल्ट। आय कर आयुक्त v. एस. पिचार्डमनिकन चेट्टियार 1984 (147) आई. टी. आर. 251; आयकर आयुक्त, बिहार बनाम। एम/एस। सहाय प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कं. (पी) लिमिटेड 1983 (144) आई. टी. आर. 357; भगवानदास नारायणदास बनाम। के आयुक्त आयकर, अहमदाबाद और अन्य 1973 खंड। 98 आई. टी. आर. 194; आयकर आयुक्त बनाम एम. के. गैब्रियल बाबू और अन्य (1991) 188 आई. टी. आर. 464 केरल और धनुष जनरल स्टोर बनाम। आयकर आयुक्त (2011)

339 आई. टी. आर. 651 छत्तीसगढ़-संदर्भित।
(सहमत):

पकड़ना: (प्रति हृषिकेश राय, जे.)

1. यदि नाममात्र मूल्य की सभी विभिन्न वस्तुएं मूल्यवान वस्तु के कोष्ठक हैं, तो यह एक बेतुकी बात की ओर ले जाएगी जो विधायी इरादे के साथ भी असंगत होगी।

इन [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी वस्तु के उच्च कुल मूल्य, उसके कम प्रति इकाई मूल्य को नजरअंदाज करने का मतलब धारा 69 ए के तहत कम लागत वाली साधारण वस्तुओं को भी मूल्यवान श्रेणी में शामिल करना होगा। यह इनकार करेगा

विधायिका का तर्क। इस संदर्भ में, जब एजुस्टेड जेनरिस के सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो धारा 69 ए में पूर्ववर्ती शब्द जैसे कि धन, सोना-चांदी, आभूषण से पता चलता है कि 'अन्य मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश जो उन शब्दों का अनुसरण करता है, केवल उच्च मूल्य की वस्तुओं को शामिल करने को उचित ठहराएगा। धारा 69 ए के पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित विशिष्ट वस्तुओं की उपेक्षा करके 'अन्य मूल्यवान वस्तु' या 'मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश को पढ़ने का कोई अन्य तरीका गलत होगा और सादे भाषा में हिंसा करेगा।

प्रावधान और विधायी इरादे से परे यात्रा करेंगे। इसके अतिरिक्त, उक्ति 'नोस्किटुर ए सोसाइटिस' अर्थात् (एक शब्द जिसे इसके सहयोगियों द्वारा जाना जाता है) भी उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि अन्य मूल्यवान वस्तुएं चांदी की छड़ की प्रकृति की वस्तुएं होनी चाहिए, या आभूषण या पैसा यानी केवल उच्च कीमत वाली वस्तु। [पैरा 10 और 11] [594 जी-एच; 595-ए-बी]

2. आय की धारा 69 ए की व्याख्या करने के उद्देश्यों के लिए

कर, अधिनियम 1961-साधारण और शाब्दिक अर्थ चुना जाना चाहिए क्योंकि कानून में शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं। इस प्रावधान में किसी जोड़ या घटाव की आवश्यकता नहीं है।

अपने पैरों पर। 'मूल्यवान लेख' वाक्यांश का अर्थ केवल एक ऐसी वस्तु होगा जो 'बहुत अधिक धन के लायक' हो। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है, जैसा कि आक्षेपित क्रम में कहा गया है, 'किसी भी मूल्य की वस्तु' को शामिल करना। धारा 69 ए के संदर्भ में, अस्पष्टीकृत मूल्यवान वस्तु उच्च मूल्य की वस्तु होनी चाहिए जो आय को छिपाने के लिए, कर देयता से बचने के लिए खरीदी जाती है। 'मूल्यवान लेख' वाक्यांश के लिए एक व्यापक व्याख्या को अपनाना और इस तरह इसके दायरे में किसी भी प्रकार की वस्तु को शामिल करना, जो भी मूल्य का हो, अनुचित पाया जाता है। यह भी दोहराया जाना चाहिए कि, आम तौर पर, कराधान कानूनों सहित राजकोषीय कानूनों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और कर को सादृश्य, अनुमान या उनके द्वारा उपयोग किए गए वाक्यांशों के विस्तार के माध्यम से नहीं लगाया जाना चाहिए।

विधायिका। [पैरा 15] [596-ई-जी]

3. धारा 69 ए के संदर्भ में बिटुमेन एक मूल्यवान वस्तु नहीं है और यहां निर्धारिती संबंधित का मालिक नहीं था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए के उद्देश्य के लिए बिटुमेन। [पैरा 19] [597-एच] एम/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त

धनुष जनरल स्टोर्स बनाम। आयकर आयुक्त

(2011) 339 आई. टी. आर. 651-स्वीकृत।

बनारसी देवी बनाम। आईटीओ [1964] 7 एससीआर 539 और ऑगस्टन

टेक्सटाइल कलर्स लिमिटेड v. उद्योग निदेशक और ए. एन. आर. (सिविल

अपील सं. 2830/2022) (2022) 6 एससीसी 626; सी. आई. टी वी.
कस्तूरी 237 आईटीआर 24 (एससी); डी. एन. सिंह बनाम। कमिश्नर

आयकर और ए. एन. आर. (2010) 324 आईटीआर 304; नया
शोरॉक स्पनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम एन. वी

रावल (1959) 37 आई. टी. आर. 41 और कैपी ब्रांडी सिंडिकेट बनाम।

अंतर्देशीय राजस्व (1921) 1 के. बी. 64 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

के. एम. जोसेफ के निर्णय में, जे.

(2022) 9 एस. सी. सी 186

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1981] 1 एससीआर 720

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

(1988) 3 एस. सी. सी. 588

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[2007] 8 एससीआर 496

2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित

9 पैरा 31 को संदर्भित

[2000] 2 एससीआर 665

पैरा

37

[2000] 2 एससीआर 538

पैरा 38

[1972] 1 एस. सी. आर. 239

पैरा

50

[1986] 3 एससीआर 1072

पैरा 52

[1997] 1 पूरक। एससीआर 394

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[1999] 2 पूरक। एससीआर 182

8 को संदर्भित 9 को संदर्भित

पैरा 55

[2013] 3 एससीआर 1082

पैरा

56

(2012) 13 एससीसी 488

1 को संदर्भित किया गया

पैरा 74

[1990] 2 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा 75

हृषिकेश रॉय के फैसले में, जे।

[1964] 7 एससीआर 539

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(2022) 6 एस. सी. सी. 626

संदर्भित किया गया है

14 [2023] 7 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 3738

3739 2023 तक।

सी. आर. सं. 102 में दिनांकित 18.12.2017 के निर्णय और आदेश से

2009 का और पटना में उच्च न्यायालय के 2002 के एम. ए. सं. 214 में दिनांक 05.03.2009।

रमेश पी. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता।, दिग्गज पाठक, श्रीमती श्वेता शर्मा,

रोहित प्रिया रंजन, सुश्री प्राची कोहली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., सुश्री दीक्षा राय, शुभांशु पाडी, सौरभ

मिश्रा, उदय खन्ना, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

के. एम. जोसेफ, जे.

सूचकांक *

ए.

तथ्य।

2

बी.

दलों की प्रस्तुतियाँ..

..... 15

सी.

..... 18

विश्लेषण।

कैरियर, एक बेली?

..... 30

डी.

ई.

द कैरिज बाय रोड एक्ट, 2007।

..... 34

एफ.

विश्वास का आपराधिक प्रकोप।

..... 35

..... 36

जी.

वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930।

क्या एक तिहाई मालिक है? स्वामित्व अवैध होना। 37

एच.

आई.

... .. 41

सिरकुलर की तारीख 07.07.1964

दिनांकित विभागीय निर्देश

जे.

..... 42

11.05.1994

के. R.B.JODHA उच्च न्यायालय द्वारा विभाजित पुरुष। 43

एल.

" अन्य मूल्यवान लेख "।

..... 75

एम. प्रिंसिपल ऑफ एजुसडेम जेनरिस; नॉसिटर ए

..... 81

एसओसीआईआईएस।

एन.

अन्य बिटुमेन अन्य मूल्यवान है

..... 85

लेख '।

* एड। ध्यान दें: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

A. तथ्य

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। आक्षेपित आदेश में शामिल मूल्यांकन वर्ष 1996-1997 है। अपीलार्थी ने एक पुनरीक्षण याचिका, अर्थात् 2009 की पुनरीक्षण याचिका सं. 102 दायर की। 18.12.2017 दिनांकित आदेश द्वारा, समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई। तदनुसार, दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

5. मीडिया में एक घोटाले की खबर आई थी। इस घोटाले में बिटुमेन के ट्रांसपोर्टर शामिल थे, जो तेल कंपनियों से उठाए गए थे, बिटुमेन का दुरुपयोग किया गया था और उठाए गए मात्रा को बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के विभिन्न प्रभागों तक नहीं पहुंचाया गया था। अधिनियम के तहत मूल्यांकन में घोटाले का असर पड़ा।

6. यह सब शुरू हुआ, जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, निर्धारण वर्ष 1995-1996. By में एक मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.03.1998 पारित किया जा रहा है, मूल्यांकन अधिकारी ने घोटाले पर ध्यान देते हुए, 23.01.1998 का कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने 14507.81 मीट्रिक टन बिटुमेन उठाया था, लेकिन केवल 10064.1 मीट्रिक टन वितरित किया था। इसका मतलब था कि अपीलार्थी ने 4443.1 मीट्रिक टन वितरित नहीं किया था। अपीलार्थी ने चालान की फोटोकॉपी प्रस्तुत की ताकि यह स्थापित किया जा सके कि बिटुमेन वितरित किया गया था। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कार्यकारी अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं को समन जारी किया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि श्री मदन प्रसाद और अहिया अंसारी को छोड़कर सभी कनिष्ठ अभियंताओं ने बिटुमेन के वितरण के तथ्य को स्वीकार किया। वास्तव में, मूल्यांकन अधिकारी ने देखा कि केवल उन्हीं कनिष्ठ इंजीनियरों ने बिटुमेन की रसीद स्वीकार की, जहां प्रभारी इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर ने डिलीवरी स्वीकार की। श्री मदन प्रसाद ने इस बात से इनकार किया कि जिस हस्ताक्षर पर कथित तौर पर उनका हस्ताक्षर था, वह उनके हस्ताक्षर नहीं थे। मूल्यांकन अधिकारी ने पाया [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि कनिष्ठ इंजीनियरों ने डाक टिकट लगाने से इनकार कर दिया और यह स्थिति ली कि यदि डाक टिकट है, तो उसे अनुभाग का नाम इंगित करना चाहिए। आकलन अधिकारी ने यह पता लगाकर कि 4443.80 मीट्रिक टन बिटुमेन वितरित नहीं किया गया था, Rs.21985700/- का योग जोड़ा। यह अधिनियम की धारा 69 ए को लागू करके किया गया था।

7. कालानुक्रमिक रूप से, यह न्यायालय नोटिस करता है कि मूल्यांकन वर्ष 1996-1997 के लिए, मूल्यांकन अधिकारी ने 31.03.1999 दिनांकित आदेश पारित किया। द.

अपीलार्थी ने अपने विवरणी में Rs.676133/- के शुद्ध लाभ का खुलासा किया। जाँच पर, निर्धारण अधिकारी ने फिर से घोटाले को देखा और पाया कि जबकि अपीलार्थी द्वारा 10300.77 मीट्रिक टन उठाए गए थे, केवल 8206.25 मीट्रिक टन वितरित किए गए थे। तदनुसार, यह पाया गया कि 2094.52 मीट्रिक टन की आपूर्ति नहीं की गई थी। उक्त आधार पर और फिर से आह्वान करते हुए

अधिनियम की धारा 69 ए, रुपये की राशि। 10471720.30 अपीलार्थी की आय के रूप में जोड़ा गया था।

8. निर्धारण वर्ष 1995-1996 के लिए दिनांकित 27.03.1998 आदेश के विपरीत, अपील में, दिनांकित 15.09.2000 आदेश द्वारा, आयुक्त अपील ने पाया कि दो को छोड़कर सभी कनिष्ठ अभियंताओं ने स्वीकार किया था।

वितरण। यह पता लगाने के बाद कि मात्रा के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया जोड़, जहां जूनियर इंजीनियरों ने डिलीवरी स्वीकार कर ली थी, असमर्थनीय था, अपीलीय प्राधिकरण ने कुल राशि को हटाने का आदेश दिया।

Rs.20114659/-। यह राशि 4064.28 मीट्रिक टन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विवादित मात्रा के संबंध में, अर्थात्, श्री मदन प्रसाद और जूनियर इंजीनियर अहिया अंसारी द्वारा उठाया गया विवाद, मामला था

जिरह का अवसर देने के लिए वापस भेज दिया गया। यह आदेश मूल्यांकन वर्ष 1995-1996 से संबंधित है।

9. कालानुक्रमिक क्रम में अगला, अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 18.12.2000 आदेश है।

निर्धारण वर्ष 1996-1997 से संबंधित दिनांकित 31.03.1999 आदेश के विरुद्ध। अपीलीय प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के मूल्यांकन का उल्लेख किया। अपीलार्थी के मामले में यह योग्यता पाई गई कि दो कनिष्ठ इंजीनियरों को छोड़कर, अन्य ने डिलीवरी को स्वीकार कर लिया था। Rs.10471720/- को जोड़ने का आदेश दिया गया था।

10. राजस्व ने आयकर के दरवाजे खटखटाये-कर अपीलीय

दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए न्यायाधिकरण (इसके बाद संक्षेप में 'आई. टी. ए. टी.' के रूप में संदर्भित)।, 1995-1996 और 1996-1997। मूल्यांकन वर्ष 1995-1996 के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के संबंध में, आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान एक और विकास हुआ। आवेदन दिनांक 07.02.2001 द्वारा, राजस्व, धारा/धाराओं का आह्वान करते हुए।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.] अधिनियम के, दिनांकित 15.09.2000 आदेश में सुधार की मांग की गई। इस आईकेशन को 31.05.2001 दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी गई। वह यह है कि

ध्यान दिया:

" यह भी देखा गया है कि हालांकि अपीलीय आदेश के पृष्ठ 4 पर मेरे विद्वान पूर्ववर्ती ने उल्लेख किया है कि "आयकर के सहायक आयुक्त ने यह भी कहा है कि केवल उन जूनियर इंजीनियरों के पास था।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बिटुमेन प्राप्त हुआ था जिसमें डिबीजन के कार्यकारी अभियंता और मुख्य अभियंता ने भी दिखाया था कि बिटुमेन प्राप्त हुआ था। लेकिन अपीलीय आदेश के पृष्ठ 7 और 8 पर निष्कर्ष देते समय वह इस तथ्य से चूक गए हैं।

यह मानते हुए कि जूनियर इंजीनियरों ने पुष्टि की थी

इंजीनियर इन चीफ की रिपोर्ट के अनुसार बिटुमेन की 4443.80 मीट्रिक टन की कुल कम आपूर्ति में से 4064.28 मीट्रिक टन बिटुमेन की प्राप्ति। ऊपर दिए गए प्रासंगिक पैरा को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह निष्कर्ष देते समय CIT (A) इस धारणा में था कि 4443.01 मीट्रिक टन की कुल कम आपूर्ति के संबंध में जैसा कि इंजीनियर इन चीफ और जूनियर ने बताया था। इंजीनियर ने बिटुमेन की रसीद स्वीकार कर ली थी, जिसमें दो नाम थे- I) श्री मदन प्रसाद।

और II) श्री अहिया अंसारी स्वतंत्रता के दौरान

ए. ओ. द्वारा समन जारी करके पूछताछ की जाती है। इस प्रकार, मेरा मानना है कि मेरे पूर्ववर्ती ने रुपये की राहत दी है। 2,01,14,659 / - 40.64.28 एमटी के संबंध में। की गलत धारणा के तहत बिटुमेन का

तथ्य यह है कि जूनियर। इंजीनियरों ने 4064.98 एमटी की प्राप्ति की पुष्टि की थी। ए. ओ. के समक्ष अपने बयानों में बिटुमेन के मामले में श्री मदन पी. डी. और श्री अहिया अंसारी जिन्होंने बिटुमेन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, मेरे एलडी। पूर्ववर्ती ने अपीलार्थी को जिरह करने का अवसर देने के बाद मामले को फिर से तय करने के निर्देश के साथ मामले को ए. ओ. की फाइल में अलग कर दिया था।

ये दोनों जूनियर। इंजीनियरों और आगे की पूछताछ करने के बाद

चालानों पर उनके हस्ताक्षरों की वास्तविकता या अन्यथा स्थापित करने के लिए, मैं एओ की फाइल में बिटुमेन के संबंध में 659/- रुपये के इस जोड़ को इस निर्देश के साथ अलग रखना उचित समझता हूं कि वह संबंधित जूनियर को समन जारी करेगा। जिन इंजीनियरों ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार 4064.98 मीट्रिक टन बिटुमेन प्राप्त किया है, वे अपने बयान दर्ज करते हैं, अनुमति देते हैं अपीलार्थी को उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर और, यदि

आवश्यक है, ऐसे हस्ताक्षरों की वास्तविकता स्थापित करने के लिए उनके हस्ताक्षर हस्तलेखन विशेषज्ञों को भेजें। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठ पर अंतिम पैरा-[2023] 7 एस. सी. आर. के प्रतिस्थापन के क्रम में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 सी. आई. टी. (ए) के पृष्ठ 8 के रूप में पहले तक विस्तारित है या जो पहले से ही है

ऊपर निम्नलिखित पैरा द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है:

केवल 2 जूनियर। इंजीनियर अर्थात्, 1. श्री मदन प्रसाद, 2. श्री अहिया अंसारी से आपूर्ति में
कमी के संबंध में पूछताछ की गई है।
4443.01 एम. टी. का बिटुमेन। श्री मदन प्रसाद और श्री अहिया अंसारी

ए. ओ. इस कम आपूर्ति के संबंध में मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता से प्राप्त रिपोर्ट को
प्रतिबंधित करता है। केवल मुख्य/कार्यकारी अभियंताओं में अभियंता की ऐसी रिपोर्ट के आधार पर; ए. ओ.,
659/- रुपये मूल्य के बिटुमेन की कम आपूर्ति के कारण जोड़ना उचित नहीं है, मैं ए. ओ. की फाइल में
659/- रुपये के इस जोड़ को इस निर्देश के साथ अलग रखना उचित समझता हूं कि वह इसके लिए समन
जारी करेगा। संबंधित

जूनियर। जिन इंजीनियरों ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार 4064.28 मीट्रिक टन बिटुमेन प्राप्त
किया है, वे अपना बयान दर्ज करते हैं, अपीलार्थी को उनकी जांच करने का अवसर देते हैं और यदि आवश्यक
हो, तो अपने हस्ताक्षरों को हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं।

ऐसी वास्तविकता या अन्यथा स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ

हस्ताक्षर, इन निर्देशों को पूरा करने के बाद कोई भी जोड़, यदि बुलाया जाता है

क्योंकि बनाया जाएगा। "

आई. टी. ए. टी. ने राजस्व और अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। क्रॉस-आपत्ति का
निपटारा किया गया। यह आदेश दिनांकित 11.01.2002 है। 12. आकलन वर्ष 1996-1997
के लिए आई. टी. ए. टी. ने राजस्व द्वारा दायर अपील और दिनांकित 18.12.2000 के आदेश के खिलाफ
दायर क्रॉस-आपत्ति का भी निपटारा किया। राजस्व [आई. टी. ए. 240 एम/एस. द्वारा दायर अपील।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

मूल्यांकन अधिकारी। इस प्रकार, उसी दिन, अर्थात्, आई. टी. ए. टी. ने राजस्व द्वारा दायर अपील को अनुमति दी और मूल्यांकन वर्ष के लिए बिटुमेन की कम आपूर्ति के कारण जोड़ से संबंधित निर्धारण अधिकारी के आदेश को कायम रखा, जबकि मूल्यांकन वर्ष के लिए, आई. डी. 2 के आदेश को ध्यान में रखते हुए। आयुक्त अपील, अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित की गई, जिसके द्वारा मामला वापस भेज दिया गया, राजस्व की अपील और अपीलार्थी की अपील, सुधार आदेश को चुनौती देते हुए,

बर्खास्त कर दिया।

13. इसने, बदले में, अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, यानी 2002 का एम. ए. 214, शुरू की। उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्यांकन वर्ष 1996-1997 के लिए विवरणी दाखिल करने वाले अपीलार्थी को संदर्भित करता है, जिसमें Rs.576133/- की कुल आय का खुलासा किया जाता है।

14. बिटुमेन की कम आपूर्ति के आधार पर रुपये 1,04,72,720.30 को जोड़ने का संदर्भ दिया जाता है। प्रस्तुतियों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 69 ए के दायरे पर ध्यान केंद्रित किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि 'मालिक' शब्द का अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ है और जब कोई ट्रांसपोर्टर माल बेचता है और उसके लिए वास्तविक मालिक की ओर से नहीं, तो वह कर के उद्देश्य से मालिक बन जाता है।

बिटुमेन उठाने और सड़क निर्माण विभाग को आपूर्ति नहीं करने के बाद, जिसे इसकी आपूर्ति की जानी थी, अपीलकर्ता उठाए गए बिटुमेन पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वितरित नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने धीरजलाल हरिदास बनाम में निर्णय को अलग किया। आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बॉम्बे ने यह नोट करते हुए कि कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण उस आय के हकदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए था। न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम में भी निर्णय में अंतर किया। अमृत लाल चुनीलाल 2 इट

1 1 (1982) 138 आईटीआर 570 2 (1984) 40 सीटीआर बॉम्बे 387।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पाया गया कि उक्त मामले में निर्धारिती को मालिक नहीं पाया गया, जबकि आई. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी को मालिक पाया। उच्च न्यायालय उक्त निष्कर्ष से सहमत हो गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर विचार किया कि धारा 69 ए में 'अन्य मूल्यवान वस्तुओं' में 'बिटुमेन' शामिल नहीं हो सकता है। अपीलार्थी का तर्क

उल्लेखनीय है कि धारा 69 ए को लागू करने के लिए बिटुमेन का धन, सर्राफा या आभूषणों के साथ कोई संबंध होना चाहिए। यह पाया गया कि कोई भी वस्तु जिसका मूल्य है, 'मूल्यवान वस्तु' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगी।

अनुच्छेद 69 ए के तहत और ऐसी वस्तु के मूल्य को निर्धारिती की आय माना जा सकता है, अगर निर्धारिती कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है या दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक होता है। यह तर्क कि धारा 69 ए लागू नहीं होगी क्योंकि अपीलार्थी ने स्पष्टीकरण की पेशकश की थी, स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह पाया गया कि एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने पर, स्वीकार नहीं किया जाने पर, धारा 69 ए का आह्वान होगा, यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। दूसरे शब्दों में, धारा 69 ए लागू हुई। अंत में, अपीलार्थी के इस तर्क के संबंध में कि बिटुमेन की लागत और उसके मूल्य को आय के रूप में नहीं जोड़ा गया था, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के पास ऐसा कोई मामला नहीं था कि उसने बिटुमेन को लागत से कम कीमत पर बेचा था। अपीलार्थी को बिटुमेन का मालिक पाया गया और इसे जोड़ा गया। यह आदेश 05.03.2009 पर पारित किया गया था।

15. इसके बाद, अपीलार्थी ने समीक्षा याचिका सं. 102 दायर की।

2009. अपीलार्थी ने यह इंगित करने का इरादा किया कि आकलन वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए तथ्यों के एक ही सेट पर दायर अलग-अलग अपीलों में, ITAT ने वर्ष 1996-97 के लिए राजस्व की अपील की अनुमति दी थी, लेकिन आकलन वर्ष 1995-96 के लिए, मामले को वापस भेज दिया गया था। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर समीक्षा में खारिज कर दिया था: तर्क:

" हालाँकि, सवाल यह होगा कि क्या यह तथ्य कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक और आदेश सही या गलत तरीके से पारित किया था, इसका कोई प्रभाव हो सकता है जिससे वर्तमान मामले में पारित न्यायाधिकरण का निर्णय गलत हो सकता है, भले ही इस न्यायालय द्वारा अपील में इसे बरकरार रखा गया हो? जवाब नकारात्मक होना चाहिए। निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए, मामला अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि खंड पीठ ने 2002 के एम. ए. No.214 में अपीलीय न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को सही होने के लिए पहले ही स्वीकार कर लिया है। एक ही न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण की एक ही पीठ का दृष्टिकोण एक अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए सही या गलत था, यह विषय वस्तु नहीं थी।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए न केवल अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बल्कि इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भी जांच की गई है। और वही सही पाया गया है।

16. अदालत ने पाया कि कोई पेटेंट त्रुटि नहीं थी। तथ्य यह है कि एक ही निर्धारिती के लिए लेकिन अलग-अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए, समान आई. टी. ए. टी. की पीठ ने बिटुमेन की कम आपूर्ति की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था क्योंकि यह उसकी जानकारी में नहीं था कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया था या नहीं, जबकि मूल्यांकन वर्ष के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय 2002 के एम. ए. 214 में इस न्यायालय तक गया था। यह 2002 के एम. ए. 214 में दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश और 2009 की समीक्षा याचिका 102 में दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश के खिलाफ है कि अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

B. दलों की प्रस्तुतियाँ

17. अदालत ने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश पी. भट और अतिरिक्त अधिवक्ता श्री एन. वेंकटरमण को सुना।

राजस्व की ओर से महान्यायवादी।

18. श्री रमेश पी. भट ने हमारे सामने दृढ़ता से आग्रह किया कि

आदेश स्पष्ट त्रुटियों को धोखा देते हैं। जब समीक्षा में त्रुटि की ओर इशारा किया गया था, हालांकि इस पर ध्यान दिया गया है, तो उच्च न्यायालय इस भ्रांति को सुधारने में विफल रहा है। संक्षेप में, तथ्यों पर त्रुटि इस प्रकार है:

" दो मूल्यांकन वर्ष शामिल हैं अर्थात् 1995-96 और 1996-97। मूल्यांकन वर्ष 1995-96 में, बिटुमेन की छोटी डिलीवरी के लिए Rs.20114659/- के योग में एक जोड़ किया गया था, जिसे वाहक के रूप में अपीलार्थी बिहार में विभाग को परिवहन और वितरित करने के लिए बाध्य था। मूल्यांकन वर्ष 1996-97 में, इसी तरह अपीलार्थी को Rs.10471720/- के योग के साथ जोड़ा गया था। "

19. यह इंगित किया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 1995-1996 के लिए, जैसा कि पहले देखा गया है, दिनांक 31.05.2001 के सुधार आदेश के आधार पर,

जिसके आधार पर, राजस्व द्वारा दायर अपील को आई. टी. ए. टी. और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ आदेश खारिज हो गया था, मामले पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार किया जाना था। वही न्यायाधिकरण, उसी दिन, अर्थात्, 11.01.2002, [2023] 7 एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी ओर, राजस्व की अपील को अनुमति दी और दिनांकित 18.12.2000 आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसके द्वारा आयुक्त अपील ने बिटुमेन की कथित गैर-डिलीवरी के आधार पर हटाने का आदेश दिया था। वास्तव में, यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय दिनांकित 05.03.2009 आदेश में नोट करता है, जैसे कि

अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष 1995-1996 के विरुद्ध अपील दायर की गई थी। यहां तक कि जब न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी विचारों को पुनर्विचार याचिका में इंगित किया गया था, तब भी तर्क पर ध्यान देने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण के इसे खारिज कर दिया है। आदेश में, यह बताया गया है कि न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1995-1996 के लिए मामला था

2012 के एम. ए. 214 में न्यायालय की यात्रा की, जब यह वास्तव में 1996-1997 से संबंधित था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान वरिष्ठ वकील यह तर्क देंगे कि बिटुमेन को अधिनियम की धारा 69 ए के अर्थ के भीतर अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है। शब्दों की वही संगति, जिसमें 'अन्य मूल्यवान लेख' शब्द पाए जाते हैं, पैसा, सोना और सोना, जोड़ को अवैध ठहराने के लिए न्यायालय को राजी करना चाहिए था। हमारे सामने यह भी प्रचार किया गया था कि अपीलार्थी को मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि अपीलार्थी एक वाहक था। इसने विचाराधीन वस्तुओं को उठाकर अपने दायित्वों को पूरा किया और उन्हें वितरित किया। वास्तव में, यह अपीलार्थी का तर्क है कि माल वितरित किया गया था और कोई गबन नहीं हुई थी। जिन तेल कंपनियों से बिटुमेन उठाया गया था, उनसे डिलीवरी कम होने की कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि प्रेषक विभाग से भी कोई शिकायत नहीं थी। जिरह का अधिकार दिया जाना चाहिए था। अपना मामला साबित करने के लिए भार विभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील निम्नलिखित मामले कानून से समर्थन प्राप्त करेंगे:

(1984) खण्ड 147 आई. टी. आर. 251; अतिरिक्त। आय आयुक्त

आई.

कर V. एस. पिचार्डमनिकन चेट्टियार।

(1993) खण्ड 199 आई. टी. आर. 370; मोहन बी. समतानी बनाम।

ii.

आय आयुक्त-कर।

20. अपीलार्थी तर्क देगा कि निष्कर्ष यह है कि

डिलीवरी चालानों की फोटोकॉपी गढ़ी गई थी जो एक बड़ी त्रुटि थी। अपीलार्थी के पास एक मामला है कि यह अधिक इसलिए है क्योंकि दो कनिष्ठ अभियंता प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित होने में विफल रहे थे।

21. अपीलार्थी ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। ए.
बालकृष्णन और अन्य 3। वह. किशिनचंद में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान
आकर्षित किया

3 (2022) 9 एस. सी. सी. 186 एम/एस.

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

चेल्लाराम बनाम. आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी II, बॉम्बे। 22. अपर सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि कोई मामला नहीं बनाया गया था। वह चुहरमल (ऊपर) पर भरोसा करेगा। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

सी. विश्लेषण

23. धारा 69 अस्पष्टीकृत निवेशों से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

निम्नलिखित है:

निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले निर्धारिती ने ऐसे निवेश किए हैं जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, यदि - आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा बनाए रखा गया, और निर्धारिती आय की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है।

2 निर्धारण अधिकारी की राय में, निवेश या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

निवेशों को ऐसे वित्तीय वर्ष के निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

24. धारा 69 ए को वित्त अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम 5) डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.1964 द्वारा जोड़ा गया। वह इस प्रकार है:

“ 69 ए. अस्पष्टीकृत धन, आदि। जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती किसी धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और ऐसा धन, सर्राफा, आभूषण या मूल्यवान वस्तु उसके द्वारा आय के किसी भी स्रोत के लिए रखे गए लेखा पुस्तकों में, यदि कोई हो, दर्ज नहीं की जाती है, और निर्धारिती

धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, 4 निर्धारण अधिकारी की राय में, धन और सर्राफा का मूल्य संतोषजनक नहीं है।

आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु को आय माना जा सकता है।

ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती का।

25. धारा 69 बी निर्धारण अधिकारी को किसी निर्धारिती द्वारा सर्राफा, आभूषण और आभूषणों में किए गए निवेश से निपटने की शक्ति प्रदान करती है।

अन्य मूल्यवान वस्तु, जब ऐसी परिसंपत्तियां उनके स्वामित्व में पाई जाती हैं

4 (1980) पूरक।

सी 660 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारिती और वह उन्हें प्राप्त करने या उनमें निवेश करने के लिए खर्च की गई राशि और उसमें दर्ज राशि के बीच बेमेल पाते हैं।

आय के किसी भी स्रोत के लिए लेखा बही और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, अतिरिक्त राशि पर कर लगाया जा सकता है। धारा 69 सी, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1976 अंतःस्थापित, अस्पष्टीकृत व्यय से संबंधित है, जिसे निर्धारिती की आय माना जाता है।

26. धारा 69 और धारा 69 ए, करीबी पड़ोसी होने के अलावा, एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं। धारा 69 अस्पष्टीकृत से संबंधित है। निवेश करें। धारा 69 ए अस्पष्टीकृत धन, सर्राफा, आभूषणों से संबंधित है।

या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ। धारा 69 ए को 1964 के संशोधन अधिनियम 5 द्वारा जोड़ा गया था और यह डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1964 से प्रभावी हुआ। दोनों धाराओं में प्रावधानों की विषय वस्तु की अपेक्षा की गई है, अर्थात्, धारा 69 के मामले में निवेश और धारा 69 ए के मामले में धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। अर्थात्, ऐसे मामले में जहां लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। के मामले में

धारा 69 के तहत निवेश, अनिवार्य रूप से, कानून देने वाला निर्धारण अधिकारी के इस निष्कर्ष पर विचार करता है कि निर्धारिती ने निवेश किया था। धारा 69 ए के मामले में, निर्धारिती को धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मालिक पाया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में, यदि निर्धारिती क्रमशः निवेश और धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्रकृति और स्रोत के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम है, और यह असंतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो किसी भी धारा के तहत कोई मानित आय नहीं हो सकती है।

27. धारा 69 ए की ओर अधिक ध्यान देते हुए, इसे निम्नलिखित आवश्यक भागों में विभाजित किया जा सकता है:

निर्धारिती को मालिक पाया जाना चाहिए;

ए।

वह किसी भी धन, सर्राफा, आभूषण या आभूषण का मालिक होना चाहिए।

बी।

अन्य मूल्यवान वस्तुएँ;

उक्त लेखों को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए

सी।

खाता, यदि कोई रखा गया हो;

निर्धारिती इस संबंध में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है
डी।

विचाराधीन वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रकृति और स्रोत;

या

जो स्पष्टीकरण दिया जाता है, वह अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, तो, का मूल्य

ई.

सर्वाफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु को उस वित्तीय वर्ष की आय माना जा सकता है जिसमें निर्धारिती मालिक पाया जाता है।

धन के मामले में, धन को माना जा सकता है

एफ.

वित्तीय वर्ष की आय;

28. मामले के तथ्यों पर प्रावधान को लागू करते हुए, यह देखा जाता है कि जो बिंदु उत्पन्न होते हैं वे इस प्रकार हैं:

सवाल यह उठेगा कि क्या अपीलार्थी ऐसा कर सकता है

आई.

बिटुमेन के मालिक के रूप में माना जाए;

आगे सवाल उठेगा कि क्या बिटुमेन

II.

अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में माना जा सकता है;

तीसरा, सवाल यह उठता है कि इसका मूल्य क्या है?

III.

बिटुमेन का पता लगाया जाना है;

क्या आई. टी. ए. टी. ने विरोधाभासी आदेश पारित करने में गलती की है

IV.

मूल्यांकन वर्ष 1995-1996 और 1996-1997, उसी दिन पारित आदेशों द्वारा और क्या तथ्य थे

एक ही?

29. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, क्या अपीलार्थी को बिटुमेन के मालिक के रूप में माना जा सकता है, यह निर्विवाद है

कि अपीलार्थी बिटुमेन को बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के विभिन्न प्रभागों में तेल कंपनियों से उठाने के बाद, वितरित करने के लिए एक वाहक के रूप में लगा हुआ था। इससे पहले कि न्यायालय इस पहलू पर विचार करने के लिए आगे बढ़े, हम ध्यान में रख सकते हैं कि इस न्यायालय ने चुहरमल एस/ओ टाकरमल मोहनानी बनाम में दिए गए निर्णय में क्या कहा था। आयकर आयुक्त, एम. पी., भोपाल '। उक्त मामले में, अदालत निर्धारिती के शयनकक्ष से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी के दौरान निर्धारिती से जब्त की जा रही कलाई की घड़ियों से निपट रही थी। यह प्रश्न विचार के लिए था कि क्या साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 110 के अंतर्निहित सिद्धांत राजस्व को यह निष्कर्ष निकालने में सहायता करेंगे कि एक व्यक्ति, जिसके पास अधिकार है, कर सकता है।

मालिक के रूप में व्यवहार किया जाए। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 6. दूसरे शब्दों में, यह कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत का अनुसरण करता है कि सामान्य रूप से, जब तक कि इसके विपरीत स्थापित नहीं किया जाता है, शीर्षक हमेशा इसका अनुसरण करता है।

5 (1988) 3 एससीसी 588 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकार। इस मामले के तथ्यों में, निस्संदेह, याचिकाकर्ता के पास कलाई-घड़ियों का कब्जा पाया गया था। याचिकाकर्ता ने कोई सबूत पेश नहीं किया, यह साबित करने की जिम्मेदारी से इनकार किया कि विचाराधीन कलाई-घड़ियाँ याचिकाकर्ता की नहीं थीं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, और हमारी राय में सही है कि कलाई घड़ियों का मूल्य निर्धारिती की आय है।

30. जे. एस. पारकर बनाम में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद। वी. बी. पालेकर, जो जब्ती से निपटते थे

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 6. वहाँ एक तर्क उठाया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में प्रावधान जहां एक व्यक्ति को कब्जे में पाया गया था

यह साबित करने की जिम्मेदारी कि वह मालिक नहीं था, उस व्यक्ति पर थी जिसने पुष्टि की कि वह मालिक नहीं था, गलत था और कराधान की कार्यवाही के लिए लागू नहीं था। इस तर्क को खारिज कर दिया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह कहने का क्या अर्थ है कि साक्ष्य अधिनियम अधिनियम के तहत कार्यवाही पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, यह था कि साक्ष्य अधिनियम में निहित साक्ष्य के नियमों की कठोरता लागू नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कर लगाने वाले अधिकारी अपने समक्ष कार्यवाही में अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करने के इच्छुक थे, उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। दूसरा, वह सब जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 करती है यह है कि यह सामान्य कानून न्यायशास्त्र के एक हितकारी सिद्धांत का प्रतीक है जो परिस्थितियों के एक समूह की ओर आकर्षित हो सकता है जो इसकी संतुष्टि करता है

शर्त "।

31. उक्त दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय ने कर, सलेम बनाम आयुक्त मामले में किया है। के. चिन्नाथम्बन '। इसमें न्यायालय के बीच

एल्ड:

" 8. उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अधिनियम की धारा 69-ए में उपयोग की गई "आय" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ है जिसका अर्थ कुछ भी है जो लाभ में आया या जिसके परिणामस्वरूप हुआ।

32. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सड़क द्वारा वहन 2007 की धारा 15, जिसने वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त कर दिया था, निम्नानुसार प्रदान करती है:

" 15 प्रेषक के चूक होने के मामले में सामान्य वाहक का अधिकार।

(1) यदि प्रेषक दिए गए नोटिस की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर माल की किसी भी खेप की डिलीवरी लेने में विफल रहता है।

4) 94 आईटीआर 616 (बॉम एचसी) 7) 7 एस. सी. सी. 390 एम/एस.

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

सामान्य वाहक द्वारा, ऐसी खेप को इस प्रकार माना जा सकता है - दावा नहीं किया गया: बशर्ते कि खराब होने वाली खेप के मामले में,

तीस दिनों की अवधि लागू नहीं होगी और खेप को नोटिस की सेवा के चौबीस घंटे या किसी भी कम अवधि के बाद लावारिस माना जाएगा, जिस पर आम वाहक और प्रेषक के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक लावारिस खेप के मामले में,

सामान्य वाहक हो सकता है,

(क) यदि ऐसी खेप खराब होने वाली प्रकृति की है, तो इसका अधिकार है -

माल को बेचना; या

(ख) यदि ऐसी खेप खराब होने वाली प्रकृति की नहीं है, तो प्रेषक या प्रेषक को नोटिस भेजें।

यदि प्रेषक उपलब्ध नहीं है, तो उसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर माल को हटाने की आवश्यकता होती है और सूचना का पालन करने में विफलता के मामले में, सामान्य वाहक को ऐसी खेप को बेचने का अधिकार होगा, बिना किसी और सूचना के प्रेषक या प्रेषक को,

जैसा कि मामला हो सकता है।

(3) सामान्य वाहक, उप-धारा (2) के तहत प्राप्त बिक्री आय में से माल दुलाई, भंडारण के बराबर राशि अपने पास रखेगा।

और बिक्री के लिए किए गए खर्चों सहित अन्य देय शुल्क, और ऐसी बिक्री आय से अधिशेष, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

, जैसा भी मामला हो, प्रेषक या प्रेषक को। (4) जब तक आम वाहक और प्रेषक के बीच अन्यथा सहमति नहीं होती है, तब तक आम वाहक मालवाहक के माल दुलाई और अन्य शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में अपने बकाया की वसूली के लिए खेप को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने या निपटाने का हकदार होगा।

डिलीवरी ले रहे हैं "।

33. इसलिए, धारा 15 के तहत, यदि प्रेषक तीस दिनों के भीतर माल की किसी भी खेप को लेने में विफल रहता है, तो खेप

दावा न किए हुए के रूप में माना जाए। तीस दिनों की अवधि घोषित की गई है।

जल्दी खराब होने वाली खेपों के लिए उपयुक्त, इस मामले में, बीस घंटे की सूचना या किसी भी कम अवधि की अवधि, जैसा कि अज्ञानी और सामान्य वाहक के बीच सहमति हो सकती है, पर्याप्त है। खराब होने वाले ज्वलन के मामले में, इस तरह की सूचना के बाद, खेप को बेचा जा सकता है। जहाँ माल खराब नहीं हो रहा है, यदि माल प्राप्तकर्ता [2023] 7 एस. सी. आर. द्वारा विफलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाहक से पंद्रह दिनों की सूचना मिलने के बाद माल को हटाने के लिए, सामान्य वाहक को बिना आगे की सूचना के खेप बेचने का अधिकार दिया जाता है। धारा 15 (3) वाहक को माल दुलाई, भंडारण और अन्य शुल्कों के बराबर राशि रखने में सक्षम बनाती है, जिसमें बिक्री के लिए किए गए खर्च भी शामिल हैं। बिक्री आय से अधिशेष को प्रेषक या प्रेषक को वापस किया जाना है। धारा 15 (4) मालवाहक द्वारा भुगतान करने में विफलता की स्थिति में वाहक को बेचने का अधिकार देती है।

माल दुलाई और अन्य शुल्क, डिलीवरी लेते समय।

34. यह न्यायालय, इस मामले में, मूल्यांकन वर्षों 1996-1997 पर विचार कर रहा है। लागू कानून वाहक अधिनियम, 1865 में निहित था।

हमारे लिए आगे रहना अनावश्यक है, क्योंकि ऐसा दोनों में से किसी के मामले में नहीं है।

पक्षकार कि अपीलार्थी कानून द्वारा प्राधिकृत तरीके से विचाराधीन बिटुमेन का स्वामी बन गया था। दूसरी ओर, अपीलार्थी का विशिष्ट मामला यह है कि अपीलार्थी कभी भी मालिक नहीं बना और यह केवल एक वाहक बना रहा। हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, यदि यह पाया जाता है कि छोटी डिलीवरी हुई है, तो इसका मतलब यह होगा कि अपीलार्थी परिवहन अनुबंध की शर्तों के विपरीत कब्जे में बना रहा।

35. मोहन बी. समतानी बनाम। आय-कर आयुक्त 3, अपीलार्थी, जिसके पास एक पैकेज पाया गया था, जिसे जब हवाई अड्डे पर खोला गया था, जिसमें नटराज और उसके आसन का एक कांस्य निष्क्रिय था, को अधिनियम की धारा 69 ए की सहायता से मालिक के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी:

" 6. अभिलेख पर तथ्यों से, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्रेषक सिक्किम राज्य व्यापार निगम था और

प्रेषक सिक्किम का चोग्याल था और निर्धारिती सिक्किम राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि था। निर्धारिती ने यह भी दावा किया कि सिक्किम का चोग्याल मालिक था और अपने ए. डी. सी. के माध्यम से दिए गए उसके मौखिक निर्देश के तहत, उसने कागजात पर हस्ताक्षर करके उसे भेजने की व्यवस्था की। वास्तव में, चोग्याल ने 30 मई, 1973 को सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर को संबोधित सिक्किम के चोग्याल के अवर सचिव के पत्र के आधार पर उक्त पैकेजों के स्वामित्व का भी दावा किया। चोग्याल संबंधित समय में एक स्वतंत्र राज्य का प्रमुख था और यदि चोग्याल के स्वामित्व के दावे को विवादित करना है, तो सीमा शुल्क अधिकारियों से मूल प्राप्त करके उक्त पत्र का सत्यापन करना आवश्यक था। केवल इसलिए कि पैकेज सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, यह वास्तव में माल के निर्धारिती के स्वामित्व को साबित नहीं करता है।

8 1993 खण्ड. 199 आई. टी. आर. 370 कलकत्ता मेसर्स।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

7. हमारे विचार में, यह स्थापित या पाया नहीं गया है कि निर्धारिती उक्त मूर्ति और पीठ का मालिक है। इसके विपरीत, सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर को संबोधित 30 मई, 1973 के उक्त पत्र से पता चलता है कि चोग्याल उक्त वस्तुओं का मालिक है। ऐसी परिस्थितियों में, निर्धारिती को उत्तरदायी ठहराने और रुपये जोड़ने का कोई कारण नहीं है। 80,000 उक्त वस्तुओं का मूल्य उसकी आय के बराबर होता।

36. उच्च न्यायालय ने चुहरमल (उपरोक्त) में अंतर करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में, निर्धारिती ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि वह वस्तु उसके कब्जे में पाई गई थी वे सिक्किम के चोग्याल के थे।

डी. एक कैरियर, एक बेली?

37. जब माल को एक सामान्य वाहक को सौंपा जाता है, तो सौंपना धारा के अर्थ के भीतर जमानत के अनुबंध के बराबर होगा।

148 अनुबंध अधिनियम, 1872 जब इसे सड़क मार्ग से ले जाने के लिए है, जैसा कि इस मामले में है। जमानत के लिए एक अनुबंध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं हो सकता है, जिस मामले में अनुबंध अधिनियम की धारा 58 जमानतदार को जमानत के उद्देश्य से उसके द्वारा किए गए आवश्यक खर्चों को बेली को चुकाने के लिए बाध्य करती है। कब्जा जमानत के लिए केंद्रीय है। [पुलॉक देखें

और भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम में मुल्ला]। अनुबंध अधिनियम की धारा 151 में घोषणा की गई है कि जमानत के सभी मामलों में बेली उसे जमानत पर दिए गए सामान की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है, जितनी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति, समान परिस्थितियों में, अपना खुद का सामान लेता है।

समान थोक, गुणवत्ता और मूल्य का माल जैसा कि माल को जमानत दी गई थी। क्या यह कहा जा सकता है कि धारा 151 में घोषित देखभाल का मानक अकेले सामान्य वाहक पर लागू होता है। विषय वस्तु समाकलन नहीं है। पटेल रोडवेज लिमिटेड बनाम बिड़ला यामाहा लिमिटेड ' , न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 31. माल के नुकसान या क्षति के लिए एक सामान्य वाहक के दायित्व के सवाल पर आते हुए, कानून की स्थिति को काफी अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी एक वाहक का दायित्व अधिक व्यापक है और दायित्व एक बीमाकर्ता का है। वाहक का पूर्ण दायित्व दो अपवादों के अधीन है: ईश्वर का एक कार्य और एक विशेष अनुबंध जिसके साथ वाहक प्रवेश करने का विकल्प चुन सकता है

ग्राहक "।

9 (2000) 4 एससीसी 91 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38. उसी वर्ष, और इससे भी अधिक, उसी खंड में, इस टी ने नाथ ब्रदर्स में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इस विषय पर बात की। एक्जिम नेशनल लिमिटेड v. बेस्ट रोडवेज Ltd.¹⁰ न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्णय दिए: -

" 14. ये प्रावधान, वास्तव में, बेली के दायित्व के बारे में अंग्रेजी सामान्य कानून नियम को शामिल करते हैं। अंग्रेजी सामान्य कानून नियम के तहत, जिस व्यक्ति को माल जमानत पर दिया गया था, उसकी देखभाल का उपाय उतना ही था जितना कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपना सामान लेता था। दूसरे शब्दों में, यह केवल लापरवाही का मामला था जिस पर दायित्व स्थापित किया गया था। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है और उतना ध्यान नहीं रखता है जितना वह अपने सामान का लेता है, तो वह नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। अंग्रेजी सामान्य कानून शासन के ये सिद्धांत इस देश में भी लागू किए गए थे।

जैसा कि इरावदी में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में संकेत दिया गया है फ्लोटिला कं. लिमिटेड बनाम बगवांदास जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा गया था

निम्नानुसार:

" वर्तमान उद्देश्य के लिए यह पूछताछ करने के लिए सामग्री नहीं है कि यह कैसे था कि इंग्लैंड का सामान्य कानून पूरे भारत में सामान्य वाहकों के कर्तव्यों और देनदारियों को नियंत्रित करने के लिए आया था। तथ्य यह है

स्वयं विवाद से परे है। इसे भारतीय विधानमंडल द्वारा वाहक अधिनियम, 1865 में मान्यता प्राप्त है, जो इस आधार पर बनाया गया एक अधिनियम है -

1830 का अंग्रेजी वाहक अधिनियम "।

" 15. इस बीच, संसद ने हस्तक्षेप किया और वाहक अधिनियम, 1865 को इस परिणाम के साथ अधिनियमित किया गया कि एक आम नागरिक का दायित्व

प्रावधानों के आलोक में वाहक पर विचार किया गया

उस अधिनियम में निहित। यह सच है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 158 उस बेलर की ओर से ले जाने के लिए माल के जमानत की बात करती है, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस धारा में उल्लिखित जमानत अनावश्यक है क्योंकि इसे विशेष रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 में निर्धारित "जमानत" के रूप में प्रदान किया गया है, जिसे इतना व्यापक कहा जा सकता है कि परिवहन के लिए किसी वाहक को "माल सौंपना" शामिल हो। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, वाहक अधिनियम, 1865 के अधिनियमन के साथ, दायित्व की सीमा

वाहक को उस अधिनियम में पाया जाना चाहिए।

" 25. हम उपरोक्त धारा 6,8 और 9 के प्रावधानों को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। धारा 6 सामान्य वाहक को अपनी सीमा निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

0) 4 एससीसी 553 एम/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

उसका दायित्व केवल तभी होगा जब यह स्थापित हो कि नुकसान या क्षति ईश्वर या राज्य के दुश्मनों (या राजा के दुश्मनों, प्रिवी काउंसिल द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक वाक्यांश) के कारण हुई थी। ब्रिटिश एंड फॉरेन मरीन इंश्योरेंस कंपनी में कलकत्ता का निर्णय। भारत के जनरल नेविगेशन और आर. एल. ई. कं. लिमिटेड, रिवर स्टीम नेविगेशन कं. लिमिटेड में असम का निर्णय V. श्याम सुंदर टी कंपनी लिमिटेड, विद्या रतन बनाम में राजस्थान का निर्णय। कोटा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड और केरल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम में केरल का निर्णय। कुन्नथ टेक्सटाइल्स, जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ने धारा 6 और 8 के अर्थ के भीतर विशेष अनुबंध के प्रभाव पर विचार किया है।

वाहक अधिनियम, 1865 और हमारी राय में, वे सही निर्धारित करते हैं

कानून "।

39. अधिनियम की धारा 69ए को लागू करने के लिए, यह अपरिहार्य है कि अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि अन्य मूल्यवान वस्तु, अन्य बातों के साथ, निर्धारिती के स्वामित्व में है। एक बेली, जो एक सामान्य वाहक है, माल का मालिक नहीं है। एक बेली जो एक सामान्य वाहक है, उसे अनिवार्य रूप से माल का अधिकार सौंपा जाएगा। जमानत का उद्देश्य सामान्य वाहक द्वारा माल प्राप्तकर्ता को या प्रेषक के निर्देशों के अनुसार माल की डिलीवरी करना है। माल की दुलाई के अनुबंध के निर्वाह के दौरान, बेली माल का मालिक नहीं बनेगा। एक के तहत अन्यथा वाहक को सौंपने के मामले में

माल की बिक्री का अनुबंध भी, वाहक का कब्जा इसे माल के मालिक में परिवर्तित नहीं करेगा।

ई. द कैरिज बाय रोड एक्ट, 2007

40. सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 की धारा 15 के तहत, वाहक, जैसा कि प्रदान किया गया है, नोटिस जारी करने के बाद, जब प्रेषक द्वारा डिलीवरी लेने में विफलता होती है, तो बिक्री के मामले में माल बेच सकता है जो एक कानून द्वारा अधिकृत है। वाहक से खरीदार माल प्राप्तकर्ता के विपरीत भी एक अच्छा शीर्षक प्राप्त करेगा। यह सच हो सकता है कि जहाँ तक [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिक्री से सामान्य वाहक द्वारा प्राप्त बिक्री आय, वह माल प्राप्तकर्ता के प्रति जवाबदेह होगा जैसा कि धारा 15 में प्रदान किया गया है

एकट करें। इसी तरह, धारा 15 (4) के तहत आने वाले मामले में, सामान्य वाहक के पास माल की वसूली के लिए माल का निपटान करने की शक्ति होगी।

प्रेषक से देय राशि। ऐसे मामलों में यदि धारा 69 ए के अन्य घटक संतुष्ट हैं, तो इसमें कोई भ्रांति शामिल नहीं हो सकती है यदि कोई निर्धारिती उस माल का मालिक पाया जाता है जिसे वह कानून के अधिकार के तहत निपटाता है।

एफ. क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट

41. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405 इस प्रकार है:

" 405. विश्वास का आपराधिक उल्लंघन जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से दुरुपयोग करता है या

उस संपत्ति को अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या निपटान करता है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें ऐसे न्यास का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का, जिसे उसने व्यक्त या निहित किया है, जिसे उसने ऐसे न्यास के निर्वहन को छूते हुए किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करता है ताकि

करो, "विश्वास का आपराधिक उल्लंघन" करता है। धारा 405 के तहत चित्रण (च) उचित है और यह इस प्रकार है

निम्नलिखित है: -

" चित्रण एफ। ए, एक वाहक, को जेड द्वारा भूमि या पानी द्वारा ले जाने के लिए संपत्ति सौंपी जाती है। एक बेईमानी से दुरुपयोग करता है

संपत्ति। ए ने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है।

जी. वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930

42. माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 39, अन्य बातों के साथ-साथ, विक्रेता द्वारा विक्रेता को बिक्री के अनुबंध के अनुसार वितरण पर विचार करती है।

प्रथम दृष्टया वाहक को खरीदार को माल की डिलीवरी माना जाएगा। यह वाहक के खरीदार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करे और माल को प्रेषक को या उसके निर्देशों के अनुसार वितरित करे। माल बिक्री अधिनियम की धारा 27 एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बिक्री से संबंधित है जो मालिक नहीं है। वह इस प्रकार है: -

" 27. व्यक्ति द्वारा बिक्री, मालिक द्वारा नहीं।

इस अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन, जहां माल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो नहीं है।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

माल का स्वामी और जो उन्हें प्राधिकरण के तहत या मालिक की सहमति से नहीं बेचता है, खरीदार माल का विक्रेता की तुलना में कोई बेहतर स्वामित्व प्राप्त नहीं करता है, जब तक कि माल का मालिक अपने आचरण से विक्रेता के अधिकार से इनकार करने से वंचित न हो।

बेचना:

बशर्ते कि, जहां एक व्यापारिक एजेंट, मालिक की सहमति से, माल या स्वामित्व के दस्तावेज़ के कब्जे में है माल, उसके द्वारा की गई कोई भी बिक्री, जब एक व्यापारिक एजेंट के व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्य करती है, तो उतनी ही वैध होगी जैसे कि उसे माल के मालिक द्वारा इसे बनाने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया था; बशर्ते कि खरीदार सद्भावना से कार्य करता है और उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

बिक्री अनुबंध का समय सूचना देता है कि विक्रेता के पास अधिकार नहीं है

बेचने के लिए।

43. एक वाहक द्वारा बिक्री स्वामित्व को पारित नहीं करती है, सिवाय इसके कि जब इसे प्रतिरक्षित किया जाता है और माल के मालिक का आचरण जो बदले में खरीदार के स्वामित्व को आरोपित करने से आर को रोक देगा। सड़क अधिनियम, 2007 द्वारा आयु की धारा 15 के तहत, एक वाहक द्वारा बिक्री की अनुमति है और यह कर सकता है

खरीदार के लिए अच्छा शीर्षक।

एच. क्या एक तिहाई मालिक है? स्वामित्व होना

इंग्लैंड।

44. क्या चोर को माल का मालिक माना जा सकता है? इस डी में, यह न्यायालय टिप्पणी में निम्नलिखित चर्चा को नोटिस करता है

पथ अयंगर का, आयकर का कानून।

" 12. साइन द्वा नाँन "स्वामित्व" है। - शब्द "पाए जाते हैं

इस खंड में उपस्थित होने वाले स्वामी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केवल यह तथ्य कि तलाशी लेने पर किसी व्यक्ति के कब्जे में कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं, इस धारा के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जब तक कि

यह स्थापित किया जाता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में वस्तुएं पाई गईं, वह उसका मालिक है। एक निर्धारिती को मालिक होना चाहिए, इससे पहले कि उसके कब्जे में किसी भी चीज़ को उसकी आय माना जा सके। यह.

चोरी की गई संपत्ति के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि चोर उसका मालिक है। धारा 69 ए को कुछ वस्तुओं के मूल्य को आय के रूप में मानने के लिए एक डीमिंग प्रावधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन उस डीमिंग प्रावधान के भीतर एक मामले को लाने के लिए तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिए। एक डीमिंग प्रावधान के मामले में अदालत को एक अवास्तविक स्थिति माननी होगी

चीजें वास्तविक होनी चाहिए। "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. आय कर आयुक्त बनाम। के. आई. पावल्ली ", एक खंड पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जहाँ आवकारी अधिकारियों को वस्तुएँ मिली थीं।

एक डिब्बे में धारा 69 ए द्वारा कवर किया गया। निर्धारिती ने स्वामित्व का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहा जिसके साथ वह शत्रुतापूर्ण शर्तों पर था। केरल के उच्च न्यायालय ने पाया कि निर्धारिती ने यह स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया कि वस्तुएँ किसी और की हैं। इस न्यायालय के लिए जो दिलचस्प है वह निम्नलिखित चर्चा है:

" 13. लेकिन निषेधात्मक कानून के लिए, कोई भी वस्तु संपत्ति होने के नाते किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि कानून किसी संपत्ति के प्रतिधारण को प्रतिबंधित करता है जिसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी संपत्ति स्वामित्व के बिना है। यहां तक कि निषिद्ध या निषिद्ध वस्तुओं का स्वामित्व भी अवैध रूप से किया जा सकता है। यह पूरी तरह से एक अलग बात है कि कानून दी गई वस्तुओं के मालिक को उन पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दे सकता है या कानून के तहत वस्तुएँ उत्तरदायी हो सकती हैं

जब्त कर लिया गया "।

46. अपीलार्थी अतिरिक्त मामले में निर्णय पर भरोसा करता है। आयकर आयुक्त बनाम एस. पिचाइमनिकन चेट्टियार ने 1984 (147) में रिपोर्ट दी।

आईटीआर 251। उक्त मामले में, यह ध्यान दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 69 ए को निर्धारिती को खोजने के बाद लागू किया गया था और एक अमीन को रेलवे स्टेशन पर सोना पाए जाने के बाद सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (बी) (ii) के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित करने के बाद राजस्व के खिलाफ निर्णय दिया:

" इस मामले में, निर्धारिती को मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा केवल वाहक के रूप में दोषी ठहराया गया है, न कि सोने के मालिक के रूप में। मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से कहा है कि माल के वास्तविक मालिक या वित्तीय धनाढ्य भूमिगत हैं। इसलिए, केवल एस के आधार पर। 110 में से

साक्ष्य अधिनियम, सोने के मूल्य को उसकी आय नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि निर्धारिती चुप रहा है और उसने सोने के मालिकों के नाम का खुलासा नहीं किया है, उसका मूल्यांकन एस के तहत नहीं किया जा सकता है। 69 आई. टी. अधिनियम का ए. एस के तहत कर लगाया जाने वाला दायित्व। 69 ए तभी उठ सकता है जब उसे माल का मालिक दिखाया जाए। "

47. दोनों विचारों का मिलान किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तुएँ हो सकती हैं और फिर भी वह कानून के दायरे में हो सकता है। धारा 69 क अपनाता। दूसरे शब्दों में, स्वामित्व की अवैधता धारा 69 ए की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकती है कि

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिकारी को निर्धारिती को वस्तु का मालिक ढूंढना चाहिए। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व पाए बिना या जब यह स्पष्ट हो कि कोई और मालिक है, तो कब्जे में पाया गया व्यक्ति, जो अवैध है, धारा 69A.The प्रश्न के तहत मालिक पाया जा सकता है।

स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है, जब एक सामान्य वाहक देने से इनकार कर देता है

खेप और अनुबंध और कानून के विपरीत इसे अपने पास रखना जारी रखता है और इसे अपने उपयोग में बदल देता है और संभवतः उसी को बेचता है, कि क्या उसे माल का मालिक पाया जा सकता है। क्या वह उस व्यक्ति से अलग होगा जो चोरी करता है और मालिक होने का दावा करते हुए उसे बेचता है। क्या चोर मालिक बन सकता है? यदि न्यायालय धारा 69 ए के अर्थ के भीतर किसी चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता देता है तो यह कानून को औचित्य से परे तनाव देना होगा। चोर को संपत्ति के मालिक के रूप में पहचानने का मतलब यह भी होगा कि संपत्ति के मालिक को मालिक के रूप में पहचाना जाना बंद हो जाएगा, जो वास्तव में सबसे चौंका देने वाला परिणाम होगा। जबकि किसी व्यक्ति का कब्जा उचित मामलों में हो सकता है, जब उसके कब्जे के स्रोत और गुणवत्ता के बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है, तो एक मूल्यांकन अधिकारी को उसे मालिक पाते हुए उचित ठहराएं, जब तथ्यों का पता चलता है कि वाहक मालिक नहीं है और कोई और मालिक है, तो उसे मालिक के रूप में वर्णित करने के लिए ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो अन्यायपूर्ण होने के अलावा सबसे अधिक अवैध हैं।

I. दिनांकित सिरकुलर 07.07.1964

48. इस संबंध में, बोर्ड द्वारा दिनांक 7 जुलाई 1964 को जारी किए गए परिपत्र की सामग्री निम्नलिखित है, अर्थात्, बोर्ड का परिपत्र संख्या 20

1964. वह इस प्रकार है:

" 86. यह प्रावधान धारा 69 के प्रावधानों का पूरक है जो उन निवेशों के मूल्य का आकलन करने में सक्षम बनाता है जो निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए हैं और जिनके स्रोत की व्याख्या उसके द्वारा नहीं की गई है।

संतोषजनक रूप से।

87. यह ध्यान से ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 69 ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें यह हैं कि (i) धन, सराफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं

आय के किसी भी स्रोत के लिए संबंधित निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में, यदि कोई हो, अभिलिखित नहीं है और (ii) यह कि निर्धारिती या तो उसके अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, आयकर अधिकारी (अब निर्धारण अधिकारी) की राय में, संतोषजनक नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि स्पष्टीकरण [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारिती द्वारा अपने मामले के समर्थन में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव संतोषजनक नहीं है, मामले में सभी तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्य पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए, निर्धारिती

के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए

यह आलोचना कि इस धारा के प्रावधानों के परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों को कठिनाई हो सकती है जिनके आभूषण या आभूषण उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए थे, को ध्यान में रखना होगा: " अक्सर लोग अपने काले धन को सोने में बदल देते हैं। वे सोने के आभूषण या सोने के बर्तन बनाते हैं और फिर कहते हैं कि यह विरासत है। बेनामी धन को किसी ऐसी चीज में लाने का यह सामान्य तरीका है जो प्रतिष्ठित हो और जिसे नकद किया जा सके। किसी भी तरह से यह (धारा 69 ए) मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को चोट पहुँचाने का इरादा नहीं है।

आम तौर पर, इसका उपयोग उन व्यक्तियों के मामलों से निपटने में किया जाएगा जो धन-कर का भुगतान करते हैं, जिन्होंने शायद 1,000 को रत्न घोषित किया है, और हम उनसे पूछ सकते हैं कि 'आपको अधिक रत्न कैसे मिले?' मैं वादा कर सकता हूँ कि यह विभाग किसी भी निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति को इस तरह से चोट नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि हमें अन्य तरीकों से वही मिलेगा जो हमारा हक है। वे बिल्कुल भी कर नहीं दे रहे हैं। हम देंगे।

उन्हें नोटिस करें। हम उन्हें कर सूची में लाएंगे। लेकिन इस प्रावधान में विचार किए गए बड़े मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भागने के लिए "।

जे. दि डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस डेट्ड

5.1994 49. यह न्यायालय मई, 1994 के विभागीय निर्देश सं. 1916 को नोटिस करता है।

" 2. विभागीय निर्देश। - निर्देश नीचे पढ़ा गया है:

" तलाशी के दौरान आभूषणों और आभूषणों की जब्ती

संचालन-के लिए दिशानिर्देश। - धारा 132 के तहत संचालन के दौरान कम मात्रा में आभूषणों की जब्ती के मामले बोर्ड के संज्ञान में आए हैं। उन स्थितियों के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण का सवाल जहां खोज दलों को आभूषण की वस्तुओं का पता चलता है, बोर्ड द्वारा जांच की गई है और सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

(i) धन-कर निर्धारिती के मामले में, घोषित सकल वजन से अधिक पाए गए सोने के आभूषण और आभूषण धन-कर विवरणी को केवल जब्त करने की आवश्यकता है।

((ii) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसका संपत्ति का आकलन नहीं किया गया है-कर, सोने के आभूषण और 500 ग्राम तक के आभूषण। प्रति विवाहित महिला 250 ग्राम। प्रति अविवाहित महिला और 100 ग्राम। प्रति पुरुष सदस्य

परिवार को जब्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) अधिकृत अधिकारी, परिवार की स्थिति और उस समुदाय की प्रथाओं और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, जिससे परिवार संबंधित है और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बड़ी मात्रा में आभूषणों और आभूषणों को जब्ती से बाहर करने का निर्णय ले सकता है। इसकी सूचना आयकर निदेशक को दी जानी चाहिए।

तलाशी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय तलाशी को अधिकृत करने वाले आयुक्त। सभी मामलों में, पाए गए आभूषणों और आभूषणों की एक विस्तृत सूची मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार की जानी चाहिए।

के. आर. बी. जोधा माल को उच्च द्वारा अपमानित किया गया

न्यायालय 50. उच्च न्यायालय ने आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम में इस न्यायालय के फैसले को अलग किया है। आयकर आयुक्त, पंजाब,

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पटियाला 1 2. उक्त में

शब्दों में, चूंकि अपीलार्थी आयकर अधिनियम, 1922 (जो अधिनियम की धारा 22 के अनुरूप है) की धारा 9 के तहत किए गए अपने दावे को स्थगित कर रहा था, क्योंकि अपीलार्थी मालिक नहीं था, इसलिए अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी का तर्क था कि संपत्ति पूरी तरह से प्रशासन के उद्देश्य से संरक्षक के पास निहित थी और निर्धारिती एक मालिक के रूप में बना रहा। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: 12 (1971) 3 एससीसी 369 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. सवाल यह है कि इस खंड में संदर्भित "मालिक" कौन है? क्या वह व्यक्ति है जिसमें संपत्ति निहित है या वह है जो संपत्ति में कुछ लाभकारी ब्याज का हकदार है? यह याद रखना चाहिए कि धारा 9 आय पर कर लगाती है।

संपत्ति में किसी व्यक्ति का हित नहीं। एक संपत्ति पर दो व्यक्तियों का स्वामित्व नहीं हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का उस पर स्वतंत्र और अनन्य अधिकार है। अतः धारा 9 के प्रयोजन के लिए, मालिक वह व्यक्ति होना चाहिए जो मालिक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, मालिक की ओर से नहीं बल्कि अपने अधिकार से।

10. एक मिनट के लिए, आइए हम चीजों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें। अगर उन हजारों विस्थापितों पर विचार किया जाता जिन्होंने व्यावहारिक रूप से पाकिस्तान में अपनी सभी संपत्तियों के साथ-साथ व्यवसायों को छोड़ दिया था उन संपत्तियों और व्यवसायों के मालिकों के रूप में जब तक "अध्यादेश" लागू था, तब उन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को अपनी संपत्तियों के वार्षिक पट्टे के मूल्य और पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़े गए व्यवसायों की आय, लाभ और लाभ के आधार पर आयकर का भुगतान करना पड़ता, हालांकि उन्हें उन संपत्तियों और व्यवसायों से एक पैसा भी नहीं मिलता था। सौभाग्य से अतीत में किसी ने भी कानून की व्याख्या उस तरह से नहीं की जिस तरह से श्री महाजन चाहते हैं कि हम व्याख्या करें। यह सच है कि कर कानूनों की व्याख्या में न्यायसंगत विचार अप्रासंगिक हैं। लेकिन उन कानूनों की, अन्य सभी कानूनों की तरह, उचित रूप से और न्याय के अनुरूप व्याख्या की जानी चाहिए।

14. कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए, अदालत द्वारा निर्धारित परीक्षण उस आय के हकदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए था। श्री महाजन द्वारा इस मामले में अंतर करने का प्रयास किया गया था

इस आधार पर कि संबंधित अंग्रेजी कानून के तहत संपत्ति से होने वाली आय के संबंध में कर का दायित्व संपत्ति के मालिक पर नहीं लगाया गया है। यह सच है कि अंग्रेजी आयकर अधिनियम, 1952 की धारा 82 को अलग तरीके से लिखा गया है। लेकिन दोनों कानूनों के अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं। यह विभिन्न से स्पष्ट है

उस अधिनियम के प्रावधान।

17. उन टिप्पणियों को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें वे किए गए थे। इसमें, उनके अधिपति इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उस देश में उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में एक निर्वासित का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिकार था। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि पाकिस्तान से निकाले गए व्यक्ति का पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति पर अवशिष्ट अधिकार है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह अधिकार एम/एस हो सकता है।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 9 के अर्थ के भीतर स्वामित्व माना जाता है

एकट करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि यह धारा कर आय को लाना चाहती है। मालिक के हाथों में संपत्ति। इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है

धारा आय की प्राप्ति पर है। "मालिक" शब्द है विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ। निश्चित रूप से

उसे पट्टे पर दी गई संपत्ति। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश (तीसरा संस्करण) में, "मालिक" शब्द के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। यह नहीं है।

हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए यह जाँचना आवश्यक है कि शब्द क्या है

धारा 9 में "स्वामी" शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह प्रावधान जो उत्पीड़न का साधन बनने में सक्षम है।

यह अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

18. इसके बाद श्री महाजन ने टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

न्यायशास्त्र पर पोलक में (6 वीं संस्करण। 1929) पीपी। 178-80 :

" स्वामित्व को शक्तियों की संपूर्णता के रूप में वर्णित किया जा सकता है

कानून द्वारा अनुमत उपयोग और निपटान। किसी चीज़ का मालिक नहीं है अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित समय पर पूरी शक्ति है

उपयोग और निपटान का; बहुत बार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमें करना चाहिए। उस व्यक्ति की तलाश करें जिसके पास ऐसी सभी शक्तियों का अवशेष है जब हम

इसके प्रत्येक अलग और सीमित हिस्से का हिसाब रखा है; और

वह मालिक होगा भले ही नियंत्रण की तत्काल शक्ति और

उपयोग कहीं और है "।

[जोर दिया

गया]

51. इस न्यायालय ने यह विचार बनाया कि आय की धारा 9 के बाद से

कर अधिनियम, 1922 में यह अपेक्षा की गई थी कि किसी व्यक्ति को घर की संपत्ति से होने वाली आय के रूप में कर का निर्धारण करने के लिए, वह मालिक होना चाहिए और पाकिस्तान में संरक्षक मालिक होने के कारण, उच्च न्यायालय का विचार सही था।

52. स्वर्गीय नवाब सर मीर उस्मान अली खान बनाम। कमिश्नर

संपत्ति कर, हैदराबाद का मामला संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत उठा। उक्त अधिनियम की धारा 2 (एम) ने शुद्ध संपत्ति को निर्धारिती की "संबंधित" संपत्तियों के संदर्भ में परिभाषित किया है। उक्त मामले में निर्धारिती ने बिक्री विलेख निष्पादित किए बिना संपत्ति बेच दी थी। पूरा विचार करने के बाद कब्जा खरीदार को सौंप दिया गया। न्यायालय निम्नलिखित कथन पर ध्यान देता है:

13 1986 (पूरक) एससीसी 700 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. इस अपील में हम जिस भौतिक अभिव्यक्ति से संबंधित हैं, वह 'मूल्यांकन तिथि पर निर्धारिती की है'। क्या पहले उल्लिखित परिस्थितियों में परिसंपत्तियाँ थीं?

अर्थात्, वे सम्पत्तियाँ जिनके संबंध में पंजीकृत विक्री विलेख निष्पादित नहीं किए गए थे, लेकिन जिनकी विक्री के लिए विचार किया गया था प्राप्त किया गया था और जिसका कब्जा खरीदारों को सौंप दिया गया था, इस उद्देश्य के लिए निर्धारिती का था

उसकी शुद्ध संपत्ति में शामिल करने के लिए? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53-ए उन परिस्थितियों में कब्जे वाले पक्ष को कब्जा बनाए रखने का अधिकार देती है। जहां पहले उल्लिखित शर्तों में एक अनुबंध निष्पादित किया गया है और खरीदारों द्वारा विक्रेता को पूर्ण विचार का भुगतान किया गया है और जहां खरीदारों को विक्रेता द्वारा कब्जे में रखा गया है, विक्रेताओं को उस कब्जे को बनाए रखने और विशिष्ट के लिए मुकदमे का विरोध करने का अधिकार है। प्रदर्शन। खरीदार औपचारिक पंजीकृत विलेख के निष्पादन के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा भी लागू कर सकते हैं यदि विक्रेता ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कानून की नजर में, खरीदारों को विचाराधीन संपत्ति के कानूनी मालिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही माना जाता है। हमारी राय में, इस मामले के उद्देश्य को इस विवाद से जोड़ना आवश्यक नहीं है कि क्या भारत में न्यायसंगत स्वामित्व के अलावा कानूनी स्वामित्व की कोई अवधारणा है या नहीं या क्या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 9 और 10 और भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 22 से 24 के तहत, जहां घर की संपत्तियों के संबंध में 'मालिक' कहा जाता है, कानूनी मालिक का अर्थ न्यायसंगत या लाभकारी मालिक नहीं है। न्यायशास्त्र पर सैलमंड, 12 वीं संस्करण।, 'पृष्ठ 246 से 264 तक' स्वामित्व के विभिन्न अवयवों पर चर्चा की गई है। 'स्वामित्व', सैलमंड के अनुसार, संबंध को दर्शाता है

विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध। सैलमंड का कहना है कि सबसे पहले, मालिक को उस चीज़ के मालिक होने का अधिकार होगा जो उसके पास है। हो सकता है कि उसके पास अधिकार न हो। दूसरा, मालिक को आम तौर पर स्वामित्व वाली चीज़ का उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार है: इसका प्रबंधन करने का अधिकार, अर्थात्, यह तय करने का अधिकार कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा; और उससे आय का अधिकार। तीसरा, मालिक को उपभोग करने, नष्ट करने का अधिकार है। या चीज़ को अलग कर दें। चौथा, स्वामित्व की अवधि अनिश्चित होने की विशेषता है। एक मालिक की स्थिति 1/S भिन्न होती है।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

जिसकी उत्पत्ति सामान्य कानून के नियमों में हुई है, जबकि न्यायसंगत स्वामित्व वह है जो इक्विटी के नियमों से अलग होता है। सामान्य कानून से। इंग्लैंड में सामान्य कानून की अदालतों ने न्यायसंगत स्वामित्व को मान्यता देने से इनकार कर दिया और न्यायसंगत स्वामित्व से इनकार कर दिया।

मालिक के रूप में मालिक। "

इसके लिए धन "निर्धारित" की संपत्ति नहीं होगी। आयकर अधिनियम के तहत निर्णयों को अलग किया गया था। इस संबंध में 3. जोधा मल (ऊपर), इस न्यायालय ने निम्नलिखित चर्चा पाई:

" 17. इस न्यायालय को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 9 और आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम के मामले में "मालिक" अभिव्यक्ति के अर्थ पर चर्चा करने का अवसर मिला था। सीआईटी [(1971) 3 एससीसी 369: ए. आई. आर 1972 एस. सी 126: (1971) 82 आई. टी. आर. 570] वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 9 के प्रयोजन के लिए,

मालिक वह व्यक्ति होना चाहिए जो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके।

मालिक, मालिक की ओर से नहीं बल्कि अपने अधिकार में। एक मूल्यांकनकर्ता

जिनकी संपत्ति निर्वासित के अभिरक्षक में निहित रही संपत्ति का मालिक संपत्ति नहीं था। यह फिर से भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 9 की अभिव्यक्ति से संबंधित है। पी. 575 (एस. सी. सी पी. रिपोर्ट के 373, पैरा 11) में इस बात पर जोर देने के लिए कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था कि

ये टिप्पणियां गुजरात उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप थीं जिन्हें हम वर्तमान में नोट करेंगे। हालाँकि, हम वर्तमान समय में इस विवाद से चिंतित नहीं हैं। यह ध्यान में रखना होगा कि धन कर के लिए देयता की व्याख्या करने में सामान्य रूप से न्यायसंगत विचार अप्रासंगिक हैं। लेकिन यह है।

यह याद रखना अच्छा होगा कि न्याय प्रशासन की योजना में, किसी भी अन्य कानून की तरह कर कानून की व्याख्या उचित रूप से और जब भी संभव हो समानता और न्याय के अनुरूप की जानी चाहिए। इसलिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधायिका द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्ति ने जानबूझकर और महत्वपूर्ण रूप से [2023] 7 एस. सी. आर. का उपयोग नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"निर्धारिती के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ" लेकिन "निर्धारिती से संबंधित परिसंपत्तियाँ", हमारी राय में, एक ऐसा पहलू है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अतः इस प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया गया और यह पाया गया कि संपत्ति निर्धारिती की बनी रही।
धन कर का उद्देश्य।

54. आयकर आयुक्त, बॉम्बे और अन्य। वी. पोद्दार सीमेंट प्रा. लिमिटेड & Ors.¹⁴, तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ के पास निम्नलिखित तथ्यों में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अवसर था। यह मामला उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय को देखते हुए अधिनियम की धारा 257 के तहत उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने के माध्यम से उठा। एक मामले में निर्धारिती ने दावा किया कि किराये की आय अन्य स्रोतों से आय के रूप में आकलन योग्य थी क्योंकि निर्धारिती कंपनी फ्लैटों की कानूनी मालिक नहीं थी। यह इस कारण से था कि संपत्ति का शीर्षक फ्लैटों के खरीदार द्वारा बनाई गई सहकारी समिति को सूचित नहीं किया गया था। एक अपील में, निर्धारिती ने दावा किया कि आय का आकलन धारा 22 के तहत किया जाना चाहिए। दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि निर्धारिती केवल पट्टेदार था और उसके पास केवल किरायेदारी के अधिकार थे। सभी मामलों में जो आम सवाल उठा वह अधिनियम की धारा 22 बनाम अधिनियम की धारा 56 का दायरा था। अधिनियम की धारा 22 घर की संपत्ति से कर आय लाती है और धारा स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि निर्धारिती को भवन या भूमि का मालिक होना चाहिए। धारा 27 का उद्देश्य धारा 22 से 26 के उद्देश्य के लिए अन्य बातों के साथ-साथ घर की संपत्ति के मालिक को परिभाषित करना है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 (ए) में निर्दिष्ट प्रकृति के अनुबंध के आंशिक प्रदर्शन में किसी भी भवन या उसके हिस्से पर कब्जा करने या बनाए रखने की अनुमति है। दरबार ने जोधा मल (ऊपर) को प्रतिष्ठित किया। इस न्यायालय ने आगे बहुत विस्तार से उल्लेख किया कि

अतिरिक्त आयुक्त में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय

आयकर, बिहार बनाम. एम/एस। सहाय प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कं. (पी) लिमिटेड 15 15. चूंकि इस न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को मंजूरी दे दी है, इसलिए इसका उल्लेख करना उचित समझा जाता है:

" 32. विद्वान न्यायाधीशों ने पृष्ठ 361 पर कहा:

" इसलिए, इस वैधानिक प्रावधान में जोर दिया गया है कि इस धारा के तहत कर स्वामित्व के संबंध में है। लेकिन यह बात

14 (1997) 5 एससीसी 482 15 1983 (144) आईटीआर 357/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

उतना सरल नहीं जितना दिखता है। यह हमें एक अधिक परेशान करने वाले प्रश्न पर छोड़ देता है कि स्वामित्व क्या है। क्या मूल्यांकन उस व्यक्ति के हाथों किया जाना चाहिए जिसके पास कानूनी अधिकार है या उस व्यक्ति के हाथों किया जाना चाहिए जिसके पास व्यावहारिक अर्थों में संपत्ति के मालिक का अधिकार है? केवल व्यावहारिक अर्थों में मालिक के रूप में आनंद का श्रेय संदर्भ में 'मालिक' शब्द को दिया जा सकता है।

इस धारा का एक व्यक्ति जो मालिक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और अपने लिए संपत्ति से आय का हकदार है।

लाभ होता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है, और दोनों पक्षों के विद्वान वकील आपस में भिड़े नहीं थे, कि इस धारा को हेगड़े की भाषा का उपयोग करने के लिए इसे उत्पीड़न का साधन बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जे., जोधा मल [(1971) 3 एस. सी. सी. 369 के मामले में: (1971) 82 आई. टी. आर. 570]

हम इस कानूनी स्थिति के प्रति बहुत जागरूक हैं कि यह सच है कि कर के बारे में कोई समानता नहीं है, कर के बारे में कोई धारणा नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है-कुछ भी निहित नहीं है। हम देख सकते हैं।

केवल उपयोग की गई भाषा पर निष्पक्ष रूप से। फिर भी, कर कानूनों की व्याख्या उचित रूप से और न्याय के अनुरूप की जानी चाहिए। यह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

इसलिए, हमें उस विशेष धारा के संदर्भ में अधिनियम की धारा 22 की भाषा का न्याय और व्याख्या करनी है, और

उस संदर्भ में हम आगे एक अधिक उपयुक्त स्थान पर वापस आएंगे। इस बीच, 'स्वामित्व' की अवधारणा में जाना अप्रासंगिक नहीं होगा। आखिरकार स्वामित्व क्या है? रोमन कानून से लेकर वर्तमान स्तर पर अंग्रेजी कानून तक पढ़ें, मध्ययुगीन चरण को विभिन्न सूत्रों के साथ विभाजित किया गया है, अब कानूनी रूप से जो स्थिति उभरती है वह यह है। एक मालिक के पूर्ण अधिकार जिन्हें अब मान्यता प्राप्त है वे हैं:

' (ए) आनंद की शक्ति (जैसे, का निर्धारण

जिसका उपयोग रेस को रखा जाना है, उपज से निपटने की शक्ति जो वह चाहता है, नष्ट करने की शक्ति);

(ख) कब्जा जिसमें दूसरों को बाहर करने का अधिकार शामिल है;

(ग) अन्तरविवोस को अलग करने या प्रतिभूति के रूप में शुल्क लेने की शक्ति;

(घ) वसीयत द्वारा रेस छोड़ने की शक्ति। "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कब्जे की अवधारणा से निपटने और इस संबंध में उदाहरणात्मक मामलों और नियमों की गणना करते हुए, पैटन पी में कहते हैं। 577 खंड (x) में: ' किसी वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर इस तरह के भौतिक नियंत्रण का प्रयोग करना आवश्यक है जो वस्तु में सक्षम है, और दूसरों को बाहर करने का इरादा दिखाना आवश्यक है: '

इस संबंध में मामले का संदर्भ दिया गया है

तुबंतिया का: यंग वी. हिचेन्स और पियर्सन बनाम। पोस्ट [(1805) 3 कैन्स 175 (न्यूयॉर्क का सर्वोच्च न्यायालय)]।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जहां किसी संपत्ति का कब्जा अर्जित किया जाता है, अर्जित संपत्ति पर इस तरह के आवश्यक नियंत्रण का प्रयोग करने के अधिकार के साथ, जो वह करने में सक्षम है, यह अन्य लोगों को बाहर करने का इरादा है जो स्वामित्व के एक तत्व को दर्शाता है।

न्यायशास्त्र पर डायस द्वारा निपटा गया विषय भी इसी प्रभाव से और अधिक जोरदार प्रभाव के साथ है, (चौथा संस्करण। , पी पर।

400) : ' इसलिए, स्थिति यह प्रतीत होती है कि भूमि के स्वामित्व का विचार अनिवार्य रूप से कब्जे में रहने के 'बेहतर अधिकार' में से एक है।

और इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि संपत्ति के साथ अवधारणा अधिक है

निरपेक्ष एक। वास्तविक अधिकार से तात्पर्य है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक इसे बनाए रखने का अधिकार है, और उस हद तक एक मालिक को मालिक माना जाता है।

" फिर से, पी। 404 , विद्वान लेखक कहते हैं:

इक्विटी में मान्यता प्राप्त स्वामित्व। यह मुख्य रूप से तब होता है जब कोई ट्रस्ट होता है, जो विशुद्ध रूप से अंग्रेजी कानून के विशिष्ट ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। एक न्यास का अर्थ है दो का अस्तित्व समवर्ती स्वामित्व के प्रकार, कानून में न्यासी का और इक्विटी में लाभार्थी का।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

कानूनी और न्यायसंगत स्वामित्व के बीच का अंतर उन ऐतिहासिक कारकों में निहित है जो उनके निर्माण और कार्य को नियंत्रित करते हैं; लाभ के संदर्भ में, अंतर केवल अधिकार के बीच है, चाहे कानूनी या न्यायसंगत, और लाभकारी अधिकार '(पीपी के माध्यम से। 404-405 न्यायशास्त्र पर डायस, चौथा संस्करण) .

इसलिए, हमें उन न्यासों से जुड़े प्रश्नों में जाने की आवश्यकता नहीं है जहां एक व्यक्ति संपत्ति रखता है और आय प्राप्त करता है।

दूसरों के लिए विश्वास जो कानूनी लाभार्थी हैं। इस मामले का सार यह है कि क्या, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, किसी विशेष मामले में वास्तविक कब्जा इस तरह के कब्जे को बनाए रखने का अधिकार देता है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, उस हद तक एक मालिक को मालिक माना जाता है। संयोग से, हालांकि जोधा मल [(1971) 3 एस. सी. सी. 369 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय: (1971) 82 आई. टी. आर. 570] ने केवल यह उल्लेख किया कि स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश ने कई परिभाषाएँ दी थीं।

" " मालिक "किसी भी भूमि या किरायेदारी के किराए या लाभ के पूरे, या किसी भी हिस्से के कब्जे या रसीद में प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है; या ऐसी भूमि या किरायेदारी के कब्जे में, वर्ष दर वर्ष किरायेदार के रूप में या किसी भी कम अवधि के लिए या एक हिस्से के रूप में लागू होता है। अपनी इच्छानुसार किरायेदार। ' (स्ट्रौड्स जुडिशियल डिक्शनरी, तीसरा संस्करण। , खण्ड. 3 , पी। 2060)

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार प्रत्येक के दृष्टिकोण से न्यायिक सिद्धांत है।

अधिनियम की धारा 22 के अर्थ के भीतर 'स्वामी' शब्द के सही अर्थ को उसके व्यावहारिक अर्थों में निर्धारित करना,

इस वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य के लिए स्वामित्व के क्षेत्र से परे कानूनी अधिकार का भूसा। इसका कारण स्पष्ट है। आखिरकार, जिस पर कर लगाया जाना है या अधिक सटीक रूप से कर लगाया जाना है, उस व्यक्ति पर जो धन की प्राप्ति में संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण रखता है और जिसके पास अपने कब्जे के दावे को विफल करने का बेहतर अधिकार नहीं है या कानूनी भाषा में एक व्यक्ति जो शेष व्यक्ति रह सकता है, जैसे कि कब्जे की अवधि के अंत या विलुप्त होने के बाद, फिर से कहें, एक हजार साल? निर्धारिती के पक्ष में इस प्रश्न का उत्तर न केवल स्पष्ट अन्याय करना होगा, बल्कि बेतुका असुविधा पैदा करेगा और विधायिका को एक निरर्थक कानून का पक्षकार करार दिया जाएगा। कोई भी यथोचित और तार्किक रूप से यह कल्पना नहीं कर सकता है कि जब संपत्ति के वास्तविक भौतिक नियंत्रण में कोई व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति की पूरी आय और हड़पने का एहसास करता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए, जिसके पास इस तरह से प्राप्त आय के निपटान की पूर्ण शक्ति है, तो उसे केवल इसलिए कर के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि कानूनी स्वामित्व का एक निशान या लंबे समय में स्वामित्व का एक हिस्सा अभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अवशिष्ट स्वामित्व की शक्ति के साथ पहन सकता है जब ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न होती है जो यहां भी एक मामला नहीं है। समझौते के खंड 4 का एक सादा पाठ, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि संपत्तियों का भौतिक कब्जा निर्धारिती को हमेशा के लिए और पूरी तरह से रखने की शक्ति के साथ दिया गया है या माना जाता है।

समान रूप से वह जिस भी तरीके से सबसे अच्छा सोचता है और निर्धारिती निपटान की पूरी शक्ति के साथ सभी आय और लाभ प्राप्त करेगा

सम्पत्तियों के साथ-साथ उनकी आय भी। तब क्या यह कहा जा सकता है कि आय का प्राप्तकर्ता निर्धारिती होने के नाते केवल संपत्ति पर पूर्ण और अनन्य नियंत्रण रखता है।

तथाकथित विक्रेता की ओर से अनुमति या बाधा, जो वास्तव में कानून के तहत करने का हकदार नहीं था, जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे, धारा 22 में कर प्रावधान से मुक्त होगा।

एक्ट? हमारे विचार में उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। इसका कारण सरल है। विचार राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। निर्धारिती को संपत्ति के अनन्य और पूर्ण कब्जे में रखा गया है। इसे आय से निपटने का अधिकार दिया गया है क्योंकि यह पसंद करते हैं। इसे निपटाने और यहां तक कि अलग करने का अधिकार दिया गया है

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति। न्यायाधिकरण द्वारा केवल धारा 54 या उस मामले के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 55 का संदर्भ

इस तथ्य पर जोर देता है कि कानूनी अधिकार तब तक पारित नहीं होता है जब तक कि वाहन का विलेख विधिवत पंजीकृत न हो। समझौता लिखित रूप में है और संपत्ति का मूल्य निश्चित रूप से सौ रुपये से अधिक है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54, इसलिए, द्वारा पूर्ण अधिकार प्रदान करने को बाहर कर देगी

निर्धारिती को हस्तांतरण। हालाँकि, यह निर्धारिती के संपत्ति के कब्जे में रहने, उससे किराए और लाभ प्राप्त करने और प्राप्त करने के अधिकार को नहीं खोएगा और पूरी आय को अपने उपयोग के लिए उपयोग में लाना। तथाकथित विक्रेता को कानून में निर्धारिती (तथाकथित विक्रेता) के अधिकार को छीनने या उस पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। यह बहुत ही व्यावहारिक उद्देश्य था कि आंशिक प्रदर्शन की समानता का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 में धारा 53-ए को सम्मिलित करके पेश किया गया था। यह धारा विशेष रूप से आंशिक प्रदर्शन के सिद्धांत को उन समझौतों पर लागू करने की अनुमति देती है, जिन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे पंजीकृत नहीं हैं और उन हस्तांतरणों के लिए जो किसी भी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से पूरे नहीं किए गए हैं। इसलिए यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां हस्तांतरण कानून द्वारा आवश्यक तरीके से पूरा नहीं किया जाता है, जब तक कि ऐसा कोई प्रावधान न हो।

प्रक्रिया के अनुपालन के परिणामस्वरूप स्थानांतरण अमान्य हो जाता है। हालाँकि, एक समझौते के बीच एक अंतर है जो शून्य है और एक समझौते के बीच एक अंतर है जो कुछ ऐसा नहीं है जो विक्रेता कर सकता था और जिसने स्पष्ट रूप से या निहित रूप से करने के लिए अनुबंध किया था, और जहां एक विक्रेता सर भूमि सहित संपत्ति के अपने हिस्से को बेचने के लिए सहमत होता है, अनुबंध में एक निहित शब्द है कि वह इस तरह के हस्तांतरण के लिए आवश्यक राजस्व अधिकारियों को मंजूरी के लिए आवेदन करेगा और अदालत उसे ऐसा करने का निर्देश देगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का समझौता अमान्य है क्योंकि कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। तत्काल मामले में, समझौते के खंड 5 के संदर्भ में यह देखा जाएगा कि विकल्प दिया गया था

निर्धारिती अपनी खुशी पर सहायता परिवार (विक्रेता) द्वारा अपने पक्ष में विधिवत पंजीकृत एक वाहन को निष्पादित करने की मांग करेगा और आधिकारिक अभिलेखों में उसका नाम परिवर्तित कराएगा। निर्धारिती ने अपने विकल्प का उपयोग उन कारणों के लिए नहीं किया है जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं—संभवतः परिस्थितियों की मांग के अनुसार उपयोग करने के लिए अपने हाथों में एक दोहरा हथियार रखना। क्या अभी तक यह कहा जा सकता है कि निर्धारिती की ओर से चूक के लिए वह स्वयं यह कहने का हकदार होगा कि वह [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का मालिक नहीं है, प्राप्त कर रहा है

हर समय किराया, उपयोग को अपने उद्देश्यों के लिए विनियोजित करना

हर समय और के उदाहरण पर कोई हस्तक्षेप नहीं है

विक्रेता? क्या यह सच के लिए एक व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण हो सकता है?

धारा 22 के सार और आत्मा का निर्माण और उद्देश्य

अधिनियम का? उत्तर, हमारे विचार में, स्पष्ट रूप से नकारात्मक है और

निर्धारिती के खिलाफ। सभी लाभ लेने के बाद और अभी भी

या विक्रेता सहित किसी की ओर से बाधा जो विक्रेता हस्तांतरण की धारा 53-ए को देखते हुए
ऐसा नहीं कर सका।

संपत्ति अधिनियम, निर्धारिती अब पीछे मुड़कर यह नहीं कह सकता है कि

अपनी इच्छानुसार किसी विलेख को पंजीकृत करने में इसकी चूक के कारण

यह अधिनियम की धारा 22 के अर्थ में मालिक नहीं था।

यह कहना दोहराया जा सकता है कि यह इन तथ्यों के कारण था

स्वामित्व की शक्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण बहिष्कृत करने का अधिकार है कब्जा और संपत्ति के
अधिकार से अन्य अनिवार्य रूप से एक है

चीज़ से। इस अर्थ में, इसलिए, निर्धारिती स्वयं बन गया विचाराधीन संपत्ति का मालिक। हमारी
राय में, कोई भी निर्णय

इसके विपरीत न्यायिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा।

या तो सामान्य कानून में या इक्विटी में। किसी भी मामले में, यह नहीं होगा

अधिनियम की धारा 22 के आशय और उद्देश्य के अधीन,

जिसके संबंध में, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हम निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं

उपयोग की गई भाषा को देखें और कर कानूनों की व्याख्या की जानी चाहिए

उचित रूप से और न्याय के अनुरूप। अब तक हम निपट चुके हैं न्यायिक सिद्धांतों पर इस संबंध में
मामले के साथ जैसे कि यह एक था

पहली छाप की बात। इसलिए, अब हमें इसका उल्लेख करना है

मामला-विषय पर कानून "।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, यह पाया गया है कि अदालत ने ज्ञापन पर भी ध्यान दिया

धारा 27 से संबंधित वित्त विधेयक 1987 में प्रावधान और

1 कि संशोधन का उद्देश्य एक स्पष्ट चूक प्रदान करना था

धारा 22 में स्वामी शब्द के बारे में संदेह व्यक्त करें।

न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया कि "अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में वास्तविकताओं और अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, मालिक की आय पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कर लगाना जो संपत्ति से आय प्राप्त करने का हकदार है।

अपना अधिकार। "/S।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

55. मैसूर मिनरल्स लिमिटेड। एम. जी. रोड, बेंगलोर बनाम

यद्यपि आवास द्वारा अधिकार की सुपुर्दगी द्वारा आवंटित घर, उसके पक्ष में परिवहन का एक वास्तविक विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। इस प्रकार आवंटित घर उसके कर्मचारियों के उपयोग के लिए थे। मूल्यांकनकर्ता ने दावा किया अधिनियम की धारा 32 के तहत समझौता। अधिनियम की धारा 32 में लाभ का दावा करने के लिए एक शर्त के रूप में संपत्ति के स्वामित्व का भी उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 4. आयकर अधिनियम की धारा 32 निर्धारिती को लाभ प्रदान करती है। प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए और शब्द

उसमें उपयोग किए गए लाभ का ऐसा अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए जो निर्धारिती को विधानमंडल द्वारा निर्धारिती को दिए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने में सक्षम बनाए। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक कर प्रावधान की दो संभावित व्याख्याएँ हैं, वह है

निर्धारिती के लिए अनुकूल होने पर वरीयता दी जानी चाहिए। 5. स्वामित्व क्या है? "स्वामित्व", "स्वामित्व", "स्वामित्व" शब्द सामान्य और सापेक्ष शब्द हैं। इनका एक व्यापक और एक संकीर्ण अर्थ भी है। अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) "मालिक" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" मालिक। वह व्यक्ति जिसमें स्वामित्व निहित है,

समझौता या वाचा जो उसके अधिकार को बाधित करती है। हालाँकि, यह शब्द एक सामान्य नाम है, और इसका अर्थ उस संबंध से एकत्र किया जाना है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, और उस विषय से-जिस पर इसे लागू किया जाता है। भूमि पर लागू होने वाले शब्द का प्राथमिक अर्थ वह है जो शुल्क का मालिक है और जिसे संपत्ति के निपटान का अधिकार है, लेकिन इस शब्द में भूमि पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति या व्यक्ति भी शामिल है।

उस पर कब्ज़ा करें या खेती करें।

'स्वामी' शब्द का उपयोग उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसमें एक या अधिक हित उसके अपने लाभ के लिए निहित हैं।

106 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. उसी शब्दकोश में, "स्वामित्व" शब्द का अर्थ, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार परिभाषित किया गया है

" संपत्ति का उपयोग करने और आनंद लेने के अधिकारों का संग्रह, जिसमें इसे दूसरों को प्रेषित करने का अधिकार भी शामिल है। एक या अधिक व्यक्तियों का अधिकार दूसरों को छोड़कर किसी चीज़ को रखना या उसका उपयोग करना। वह अधिकार जिसके द्वारा कोई वस्तु विशेष रूप से किसी व्यक्ति का है, अन्य सभी व्यक्तियों के बहिष्कार का। अधिकार, आनंद और निपटान का अनन्य अधिकार; जिसमें एक आवश्यक विशेषता के रूप में नियंत्रण, प्रबंधन और निपटान का अधिकार शामिल है।

7. न्यायशास्त्र पर डायस (चौथा संस्करण, पृ. 400) कहता है:

" इसलिए स्थिति यह प्रतीत होती है कि भूमि के स्वामित्व का विचार अनिवार्य रूप से अधिकार में रहने के बेहतर अधिकारों में से एक है। और इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि संपत्ति के साथ अवधारणा अधिक है

निरपेक्ष एक। वास्तविक अधिकार से तात्पर्य है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक इसे बनाए रखने का अधिकार है, और उस हद तक एक मालिक को मालिक माना जाता है।

8. स्ट्राउड का न्यायिक शब्दकोश कई परिभाषाएँ देता है और

स्वामित्व के चित्र। ऐसी ही एक परिभाषा यह है कि किसी संपत्ति का "मालिक" या "मालिक" वह व्यक्ति होता है जिसमें (उसकी सहमति के साथ) यह कुछ समय के लिए लाभकारी रूप से निहित होता है, और जो इसका कब्जा, या नियंत्रण, या उपयोग है; उदाहरण के लिए, एक पट्टेदार, अवधि के दौरान, संपत्ति का मालिक होता है। स्ट्राउड द्वारा दी गई एक और परिभाषा है:

" ' 'मालिक' अधिकार या रसीद वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है।

किसी भूमि या किरायेदारी के किराए या लाभ के संपूर्ण या किसी भाग में से कोई भी; या ऐसी भूमि या किरायेदारी के कब्जे में, वर्ष-दर-वर्ष किरायेदार के रूप में या किसी कम अवधि के लिए या अपनी इच्छानुसार किरायेदार के रूप में। "

19. यह अच्छी तरह से तय है कि संपत्ति के दो मालिक एक साथ और एक ही अर्थ में नहीं हो सकते हैं। द.

अधिनियम की धारा 32 को लागू करने में विधायिका के इरादे को मूल्यहास के संबंध में कटौती की अनुमति देकर पूरा किया जाएगा। उस व्यक्ति को जिसमें कुछ समय के लिए भवन पर प्रभुत्व निहित है और जो इसे अपने अधिकार में उपयोग करने का हकदार है और इसे अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा है। किसी भी अलग अर्थ को निर्दिष्ट करने से विधायी/विधानों को लाभ नहीं होगा।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

इरादा। मामले को हाथ में लेने के लिए यह अपीलार्थी निर्धारिती है जो

कीमत के हिस्से का भुगतान करने के बाद, के कब्जे में रखा गया है एक मालिक के रूप में घर
और उद्देश्य के लिए इमारतों का उपयोग कर रहा है

अपना खुद का व्यवसाय। फिर भी निर्धारिती को अस्वीकार कर दिया गया है

धारा 32 का लाभ। दूसरी ओर, आवास बोर्ड करेगा

धारा 32 के लाभ से वंचित किया जाए क्योंकि इसके होने के बावजूद

कानूनी मालिक जो अपने व्यवसाय के लिए इमारत का उपयोग नहीं कर रहा था या

पेशा। हमें नहीं लगता कि इस तरह का लाभ किसी भी स्थिति में हो सकता है।

विधायिका द्वारा इरादा किया गया है। तथ्य का पता चला

हाथ में मामले में है कि हालांकि शीर्षक का एक दस्तावेज नहीं था निर्धारिती के पक्ष में आवास
बोर्ड द्वारा निष्पादित, लेकिन

आवास बोर्ड द्वारा निर्धारिती को घर आवंटित किए गए थे, भाग प्राप्त भुगतान और कब्जा
वितरित किया गया ताकि प्रदान किया जा सके

निर्धारिती पर संपत्ति पर प्रभुत्व जिसके बाद निर्धारिती ने अपने अधिकार में कर्मचारियों को
आवास आवंटित किए थे और

वे वास्तव में निर्धारिती के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। यह है।

निकायों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य ज्ञान

आवास बोर्डों की तरह, घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है और

आंशिक रूप से आवंटित-उन लोगों को भुगतान जिन्होंने उन्हें बुक किया है।

आवंटित व्यक्ति को अधिकार भी दिया जाता है ताकि वह आनंद ले सके।

संपत्ति से। दस्तावेज़ हस्तांतरण शीर्षक का निष्पादन अनिवार्य रूप से यदि आवंटि द्वारा भुगतान
की अनुसूची का पालन किया जाता है तो इसका पालन होता है। अगर

केवल आवंटित व्यक्ति ही चूक कर सकता है कि संपत्ति उसे वापस मिल सकती है।

बोर्ड। यह केवल आवास बोर्ड और के बीच का मामला है

आवंटित। कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है। भाग-द्वारा किया गया भुगतान

आवंटित व्यक्ति शीर्षक प्राप्त करने के इरादे से हैं। डिलीवरी

स्वामित्व प्रदान करने के लिए। दस्तावेजीकरण में केवल देरी होती है
पालन करने के लिए मजबूर करने का विचार
भुगतान "।

आवंटी को अनुसूची का

(जोर दिया गया)

56. अंत में, औद्योगिक ऋण में इस न्यायालय का निर्णय है
डेवलपमेंट सिंडिकेट लिमिटेड V. आयकर आयुक्त,
पुनः & Anr.¹⁷ 17. निर्धारिती किराए के व्यवसाय में लगा हुआ था
ए. एस. ई., पट्टा और अचल संपत्ति आदि। अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में, यह पट्टे पर दिया गया था
अपने ग्राहकों के लिए ईहिकल, और उसके बाद, कोई भौतिक संबंध नहीं था
वाहनों को। इसके अलावा, पट्टेदारों को पंजीकृत किया गया था

एससीसी 541 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र में वाहनों के मालिक। अधिनियम की धारा 32 के तहत किए गए मूल्यहास के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि निर्धारिती वाहनों का मालिक नहीं था। न्यायालय ने पट्टा समझौते से पाया कि यह था

इस बात पर सहमति व्यक्त की कि निर्धारिती को हर समय वाहन का अनन्य मालिक होना चाहिए। राजस्व का तर्क कि पट्टेदार का नाम मोटर वाहन के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया था अधिनियम, और इसलिए, इसे धारा 2 (30) के तहत मालिक के रूप में माना जाना चाहिए जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। यह आगे पाया गया कि यदि पट्टेदार वास्तव में था

मालिक, उसने मूल्यहास का दावा किया होगा, जो नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पूरे पट्टे के किराए का आकलन निर्धारिती के हाथों में व्यावसायिक आय के रूप में किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों में यह अपीलकर्ता-निर्धारिती था जिसे धारा 32 के तहत मूल्यहास के लाभ का दावा करने के लिए हकदार वाहनों के मालिक के रूप में माना जा सकता है। 57. इस न्यायालय को हमारे सामने तथ्यों में धारा 69 ए में 'मालिक' शब्द की सीमा तय करने के लिए कहा गया है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत है कि 'मालिक' की अवधारणा को उस संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है जिसमें अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जोधा मल (ऊपर) के मामले में, संपत्ति निस्संदेह पाकिस्तान में संरक्षक के पास निकासी संपत्ति के रूप में निहित थी। निर्धारिती उस समय हुए नुकसान के लाभ का दावा करना चाहता था जब वह मालिक नहीं रह गया था। इस न्यायालय ने उस अधिनियम के प्रभाव को ध्यान में रखा जिसके तहत पाकिस्तान में संरक्षक मालिक बन गया। उक्त मामले में निर्धारिती का दावा था कि संरक्षक केवल इस उद्देश्य के लिए मालिक था -

प्रशासन और यह कि निर्धारिती अभी भी मालिक बना रहा

यह भावना कि संपत्ति पर उनका अंतिम अधिकार था। इस अदालत ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाया कि पाकिस्तान में सभी संपत्तियों को छोड़ने वाले हजारों विस्थापितों से कर के साथ मुलाकात की जाएगी, भले ही उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया हो और उन्हें उन संपत्तियों और व्यवसायों से एक पैसा भी नहीं मिला हो। यह पाया गया कि धारा 9 के उद्देश्य के लिए, मालिक वह व्यक्ति होना चाहिए जो मालिक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, मालिक की ओर से नहीं, बल्कि अपने अधिकार से। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान से निकाले गए व्यक्ति का संपत्ति में अवशिष्ट अधिकार था। इस संदर्भ में न्यायालय ने विचार किया कि क्या उस अवशिष्ट अधिकार को पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 9 के प्रयोजनों के लिए स्वामित्व माना जा सकता है। यह अभी भी उक्त संदर्भ में ही था कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा का ध्यान आय की प्राप्ति पर है और विभिन्न संदर्भों में स्वामी शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं।

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

58. जब बात आई पोद्दार सीमेंट प्राइवेट की। लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने धारा के संदर्भ में जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखा

22 अधिनियम और उस व्यक्ति की आय पर कर लगाने के लिए अनुमोदित जो धारा 22 के तहत अपने अधिकार में संपत्ति से आय प्राप्त करने का हकदार है। हमने पटना उच्च न्यायालय के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया है।

सहाय संपत्ति मामले में अदालत। एक मालिक के पूर्ण अधिकारों को फिर से इस प्रकार दोहराया जा सकता है:

(1)

आनंद की शक्ति जिसमें करने की शक्ति शामिल है नष्ट करें।

कब्जा करने का अधिकार जिसमें बाहर करने का अधिकार शामिल है

(2)

अन्य।

(3)

इंटर विवोस को अलग करने या सुरक्षा के रूप में चार्ज करने की शक्ति।

(4)

संपत्ति को वसीयत करने की शक्ति।

59. यह न्यायालय इस मोड़ पर यह निरीक्षण कर सकता है कि किसी वाहक के पास इनमें से कोई भी अधिकार या शक्तियां नहीं हैं। यह सच हो सकता है कि एक मालिक होने के लिए, एक मालिक के सभी अधिकार और शक्तियां एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। यह सच हो सकता है कि स्वामित्व कब्जे में रहने के बेहतर अधिकार से जुड़ा हो सकता है और किसी दिए गए मामले में वास्तविक कब्जे को स्वामित्व के साथ सुसंगत किया जा सकता है। कब्जा होने के अधिकार के साथ कब्जे में होने से यह धारणा हो सकती है कि मालिक मालिक है, जब तक कि इसके लिए संकेत न हों

इसके विपरीत। लाभकारी बनियान संदर्भ में मालिक के रूप में शीर्षक वाले व्यक्ति को पहन सकता है। एक अन्य अवधारणा जो उभरती है वह है एक व्यक्ति

संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण रखने वाले धन की प्राप्ति, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे के दावे को विफल करने का बेहतर अधिकार नहीं है, इस निष्कर्ष के लिए दरवाजे खोल सकता है कि वह धारा 69 ए के अर्थ के भीतर मालिक है। एक व्यक्ति जो संपत्ति के वास्तविक भौतिक नियंत्रण में है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए पूरी आय का एहसास करता है, वह स्वामित्व की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। हस्तांतरण को पूरा

करने के लिए आवश्यक परिवहन की अनुपस्थिति किसी व्यक्ति को मालिक पाए जाने से विचलित नहीं कर सकती है। तर्क की आत्मा संपत्ति से 'उसके अधिकार में' आय प्राप्त करने का अधिकार प्रतीत होती है।

60. आइए हम इन परीक्षणों को लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या अपीलार्थी को अभिव्यक्ति के किसी भी अर्थ में मालिक के रूप में माना जा सकता है। अपीलार्थी के रूप में एक वाहक को माल सौंपा गया था। अपीलार्थी का अधिकार बेली के रूप में शुरू हुआ। न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि माल को वितरित करने के बजाय, अपीलार्थी ने माल को [2023] 7 एस. सी. आर. को वितरित नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार राज्य में विभाग के संबंधित प्रभाग। विचाराधीन माल का स्वामित्व किसी भी समय अपीलार्थी में निहित नहीं था। माल की बिक्री अधिनियम में घोषित सिद्धांतों के आधार पर संपत्ति प्रेषक से प्रेषक को हस्तांतरित की जाएगी। यह अकल्पनीय है कि उन प्रावधानों में से कोई भी

माल में संपत्ति का अपीलार्थी को पारित करना जो माल का मात्र वाहक था। आई. पी. सी. की धारा 406 इसे संपत्ति के साथ सौंपे गए व्यक्ति के लिए एक अपराध बनाती है जिसमें एक वाहक को सौंपे गए सामान का दुरुपयोग या बेईमानी से वाहक के उपयोग में परिवर्तित किया जाना शामिल है। धारा 406 के तहत एक विशिष्ट चित्रण यह स्पष्ट करता है कि एक वाहक द्वारा ऐसा कोई भी कार्य धारा 406 के तहत अपराध को आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को यह पता लगाने की प्रक्रिया में कि अपीलार्थी माल का मालिक है, अपीलार्थी द्वारा अपराध करने की अनुमति देनी होगी। दूसरे शब्दों में, इस आधार पर कि अपीलार्थी द्वारा माल की कम डिलीवरी की गई थी, अदालत को अनिवार्य रूप से यह पता लगाना चाहिए कि यह कार्य केवल एक चूक या गलती नहीं थी, बल्कि धारा 406 के तहत अपराध करने में इसे शामिल करने वाले वाहक द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य था। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को आवश्यक रूप से यह पता लगाना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास बिटुमेन बना रहा और उसका दुरुपयोग किया गया और यह इस राज्य में है कि मूल्यांकन अधिकारी को यह पता लगाना होगा कि अपीलकर्ता ने सामान को कम समय में वितरित करने और माल का कब्जा बनाए रखने के जानबूझकर किए गए कार्य से न केवल अनुबंध के विपरीत, बल्कि भूमि के कानून के भी विपरीत, दोनों वाहक अधिनियम 1865 में और दंडात्मक प्रावधानों को तोड़ते हुए।

कानून के साथ-साथ, अपीलार्थी को मालिक के रूप में माना जाना चाहिए।

61. कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। समान रूप से, किसी व्यक्ति पर इरादे के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति के कब्जे के विपरीत जिसके लिए

सभी इरादे और उद्देश्य, और अपने स्वयं के अधिकार में, घर की संपत्ति से आय अर्जित करता है, कानूनी रूप से अन्यथा, और केवल संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत आवश्यक औपचारिक हस्तांतरण के अभाव में स्वामित्व से कम हो जाता है, एक वाहक जो न केवल अधिकार की छाया के बिना कब्जे से चिपक जाता है, बल्कि जो अधिक है, दोनों अनुबंध के विपरीत और कानून भी मालिक नहीं पाया जा सकता है। वाहक का कब्जा जो जानबूझकर अनुबंध के तहत कार्य करने से इनकार करता है, लेकिन इसके विपरीत, न केवल गलत है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा मामला है जहां कब्जा स्वयं वाहक के साथ अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए किसी भी अधिकार के बिना है। कानूनी रूप से वाहक के साथ किसी भी अधिकार को मान्यता देने में शामिल होगा

वास्तविक स्वामी के अधिकार का निषेध जो यदि संपत्ति में अनुबंध के तहत माल प्रेषक को दिया जाता है और प्रेषक नहीं तो प्रेषक होता है। इस न्यायालय ने पहले ही पाया है कि अपीलार्थी एम/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर आयुक्त,

केंद्र, पटना और एक और [के. एम. जोसेफ, जे.]

संपत्ति। एकमात्र पहलू माल का कथित कब्जा था जो स्पष्ट रूप से गलत है जब यह अनुबंध और कानून की शर्तों के विपरीत अपीलार्थी के साथ जारी रहा। 62. न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि एक अवैध व्यवसाय से प्राप्त आय को वैध रूप से कर में लाया जा सकता है [ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1271 देखें]। हालाँकि, यह अधिनियम की धारा 69 ए के आह्वान को उचित ठहराने से बहुत दूर है क्योंकि उक्त प्रावधान को लागू करना अपरिहार्य है कि मूल्यांकन अधिकारी को यह पता लगाना चाहिए कि विचाराधीन वस्तुएँ वित्तीय वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में थीं। यह अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा है।

63. यह न्यायालय इस मुद्दे को दूसरे कोण से देख सकता है। धारा 69 ए को 1964 में आय प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया था जिसकी मांग की गई थी

सर्साफा और सोना जैसी मूल्यवान वस्तुओं और आभूषणों को खरीदने के अलावा इसे पैसे के रूप में भी रखकर कर से मुक्त किया जाता है। ऐसे निर्धारिती का उद्देश्य अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मालिक बन कर भी हासिल किया जाएगा। इस मामले में, क्या यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलार्थी अवैध रूप से बिटुमेन रखते हुए कर योग्य आय को छिपाने का प्रयास कर रहा था? आगे बढ़ते हुए और फिर से यह मानते हुए कि निर्धारिती के पास अवैध रूप से बिटुमेन था और उसका निपटान करने के लिए आगे बढ़े। राजस्व के तर्क में बिटुमेन का स्वामित्व अपीलार्थी को वहन के अनुबंध के विपरीत बिटुमेन के कब्जे के आधार पर और उसी का दुरुपयोग करने के इरादे से दिया जाना शामिल है, जिसमें आगे बिटुमेन की बिक्री शामिल है।

अलगाव की शक्ति रखते हैं। काफी स्पष्ट रूप से, अगर छोटी डिलीवरी का मामला है यदि स्वीकार किया जाता है, तो माल प्राप्तकर्ता का बिटुमेन पर पूरा अधिकार था और इस आधार पर आगे बढ़ रहा था कि आकलन अधिकारी का तर्क सही है, तो विभाग के पास निश्चित रूप से एक मामला था कि उसे विचाराधीन बिटुमेन प्राप्त नहीं हुआ था। किसी भी समय मालिक के रूप में बिटुमेन पर अधिकार का दावा अपीलार्थी द्वारा नहीं किया जा सकता था।

3] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी का कब्जा चोर की तुलना में बेहतर है क्योंकि कब्जे का मूल जमानत के अनुबंध के तहत था। यह भी एक ऐसा मामला नहीं है जहां कानून में उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करने वाले वाहक का कोई मामला स्थापित किया जाता है जो उसे अधिकार के रूप में माल रखने का हकदार बनाता है या उसे स्वामित्व देता है। कानून के तहत अनुमति के अनुसार दूसरा। इसलिए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करेगा कि निर्धारण अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित करने में अवैध रूप से कार्य किया कि एक अपीलार्थी 'मालिक' था और उक्त आधार पर जोड़ा गया।

एल. "अन्य मूल्यवान लेख"

64. यह अपीलार्थी का एक मामला है कि एजुस्टेड जेनरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए, बिटुमेन अपने तत्काल पूर्ववर्ती शब्दों की संगति में एक अजीब बिस्तर साथी के रूप में खड़ा होगा।, धन, सोना-चांदी और आभूषण। दूसरे शब्दों में, यह अपीलार्थी का मामला है कि बिटुमेन एक स्पष्ट गलत है और बिटुमेन को अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में मानने का विधायी इरादा नहीं हो सकता था। हमारा ध्यान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20 डी दिनांकित 07.07.1964 की ओर आकर्षित किया गया है, जिसे जारी किया गया है। { पैराग्राफ 48 देखें

65. भगवानदास नारायणदास बनाम। आयकर आयुक्त, अहमदाबाद और अन्य, सवाल, जो अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आया था, यह था कि क्या अचल संपत्ति की सावधि जमा रसीदें और स्वामित्व विलेख 'मूल्यवान चीजें या वस्तुएं' थीं, जिसके लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 112 ए के तहत कारणदर्शक नोटिस की आवश्यकता थी। धारा 132 यदि अधिनियम 'अन्य मूल्यवान वस्तुओं' अभिव्यक्ति को भी नियोजित करता है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 18. धारा 132 की उप-धारा (5) की योजना पर बारीकी से विचार करने पर हम पाते हैं कि श्री भट्ट का उपर्युक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि हमने पूर्वगामी चर्चा में पहले ही बताया है, धारा 132 की उप-धारा (5) की योजना से यह स्पष्ट है कि धारा 132 के तहत अधिकृत तलाशी के दौरान जब्त की गई "परिसंपत्तियों" को केवल किसी निर्धारिती के कर दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए रखने की उम्मीद है, जैसा कि उसकी अधोषित आय से पता चलता है।

इसलिए, "मूल्यवान वस्तु या वस्तु" शब्दों का उपयोग करके, विधायिका का जो तात्पर्य है, वह यह है कि इन शब्दों द्वारा कवर की गई परिसंपत्तियों को ऐसा होना चाहिए जो नकद में परिवर्तित किया जा सके ताकि संबंधित निर्धारिती की कर देयता, जैसा कि इन शब्दों से प्रकट हो।

18 1973 खण्ड. 98 आई. टी. आर. 194 1/एस.

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 132 वह होनी चाहिए जो अपना आंतरिक वहन कर रही हो। धन के संदर्भ में मूल्य।
इसलिए सवाल यह है कि क्या

नियत जमा रसीदें और एक से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज अचल संपत्ति वे वस्तुएँ या वस्तुएँ
हैं जो

धन के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया। जाहिर है, शीर्षक से संबंधित एक दस्तावेज़

किसी अचल संपत्ति या यहां तक कि जारी की गई सावधि जमा रसीद पर भी

किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में किसी बैंक द्वारा केवल

स्वामित्व के दस्तावेज़ जो, हालांकि बहुत अधिक साक्ष्य रखते हैं

मूल्य, किसी भी आंतरिक बाजार मूल्य को पार न करें। वे आपूर्ति करते हैं।

परिसंपत्तियों का प्रमाण जो अपने आप में मूल्यवान हैं लेकिन वे

केवल स्वामित्व के दस्तावेज होने के कारण, उन पर न तो बातचीत की जा सकती है और न ही

एक मूल्यवान विचार के लिए स्थानांतरित किया जाए। इसके तहत

साक्ष्य से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, और जो नहीं है किसी भी बिक्री योग्य ब्याज के साथ,
"मूल्यवान चीजें या वस्तुएँ" नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (5) द्वारा या तो विचार किया गया है या

नियमों के नियम 112 ए के अनुसार। रिकॉर्ड में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है

कि सावधि जमा रसीदें, जो इस मामले में जब्त की जाती हैं,

उनके साथ कोई भी अंतर्निहित बाजार मूल्य। वे केवल

निर्धारिती को देय ऋण का प्रमाण देने वाले दस्तावेज। इसी तरह, अचल संपत्ति से संबंधित
स्वामित्व के दस्तावेजों में भी शामिल हैं -

दस्तावेजों को पैसे के मामले में कोई आंतरिक मूल्य मिला है, हम हैं इस राय का कि वे उप-धारा
(5) के अंतर्गत नहीं आते हैं

अधिनियम की धारा 132 या नियमों के नियम 112 ए।

(जोर दिया गया)

66. स्वामित्व के दस्तावेज़ या सावधि जमा रसीद के विपरीत, जो

यदि, अपने आप में, निपटाया या अलग किया जाता है, तो बिटुमेन माल होगा, एच को स्थानांतरित किया
जा सकता है। बाजार में इसका मूल्य निर्भर करेगा।

उसकी गुणवत्ता। आय कर आयुक्त बनाम। एम. के. गैब्रियल बाबू

अन्य, केरल का उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या अचल संपत्ति इस पद के अंतर्गत आएगी। धारा 132 (1) के अर्थ के भीतर वस्तु या चीज़ का मूल्य

न्यायालय ने कहा:

1) 188 आईटीआर 464 केरल [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रखता है। धारा 132 (1) के पूर्ववर्ती शब्दों को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धन, सर्राफा, आभूषण, जो "अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु" से पहले होते हैं, एक वंश बनाते हैं और इसके परिणामस्वरूप, "अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु" शब्द उस संदर्भ में एक संकुचित अर्थ और व्याख्या ग्रहण करते हैं। एक सीमित अर्थ की व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों को कुछ शब्दों को दिया जा रहा है, चाहे वह एजुस्टेड जेनरिस के सिद्धांतों को लागू करने से हो या अन्यथा इसे प्रतिबंधित करने से, बहुत से क्षेत्र और कई विषयों को शामिल करने वाले न्यायिक निर्णयों का पालन किया गया था। वे अनिवार्य रूप से आयकर कानून तक ही सीमित नहीं हैं। आयकर अधिनियम के तहत शर्तों से जुड़े लोगों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा उनके निष्कर्ष के समर्थन में संदर्भित किया गया है। हम इस विचार से सहमत हैं। इसलिए, अन्य क्षेत्राधिकारों से भी उपलब्ध साहसिक निर्णयों द्वारा इसे पूरक बनाना अनावश्यक है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश (एम. के. गैब्रियल बाबू बनाम) के फैसले की पुष्टि करते हैं। आसिस्टेंट आई. टी. निदेशक (जांच) [(1990) 186 आईटीआर

435 (केर.)] "

67. हमारे सामने विवादित क्रम में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत, हनुश जनरल स्टोर्स v. आयकर आयुक्त 20,

अन्य बातों के साथ-साथ तथ्यों पर, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया:

" 13. यदि सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं में अघोषित निवेश है, जिसका लेखा पुस्तकों में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है, तो मामला एस के दायरे में आएगा। 69 अधिनियम, 1961 का ख। हाथ के मामले में, अतिरिक्त स्टॉक था, जिसे अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में रखा जा सकता है, न कि सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं में निवेश। पूरे सर्वेक्षण में यह नहीं पाया गया कि कोई सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं नहीं मिली हैं। किराना वस्तुओं को अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

14. " मूल्यवान वस्तु का अर्थ है एक ऐसी वस्तु जो मूल्यवान है और जिसकी कीमत अधिक है, न कि अन्य सामान्य वस्तुओं की, जैसा कि तत्काल मामले में होता है।

15. समर्पण की गई आय को एस के प्रावधानों के तहत मानित आय के रूप में माना जाना चाहिए था। 69 तथापि, अधिनियम, 1961 के निर्धारण आदेश में लागू किए गए गलत प्रावधान पर, यद्यपि प्रभाव एक ही है और समर्पण की गई आय समान नहीं हो सकती।

अभिनिर्धारित किया कि यह एस के प्रावधानों के तहत आय नहीं थी। 69 में से

1) 339 आई. टी. आर. 651 छत्तीसगढ़ मेसर्स।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम, 1961। इस प्रकार, कानून का सारवान प्रश्न, अर्थात (i) और

(ग) तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

(जोर दिया

गया)

68. 'मूल्यवान' शब्द को ब्लैक के नियम में परिभाषित किया गया है।

शब्दकोश इस प्रकार है:

" मूल्यवान विशेषण। एक अच्छी कीमत के लायक; वित्तीय या बाजार होना

मूल्य "।

69. 'मूल्यवान' शब्द को संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड में परिभाषित किया गया है।

शब्दकोश इस प्रकार है: -

'मूल्यवान' शब्द को फिर से एक विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लायक

बहुत सारा पैसा। बहुत उपयोगी या महत्वपूर्ण "।

70. 'पैसा' शब्द का वर्णन ब्लैक लॉ में किया गया है।

शब्दकोश इस प्रकार है: -

" पैसा। 1. द्वारा अधिकृत या अपनाया गया विनियम का माध्यम

अपनी मुद्रा के हिस्से के रूप में सरकार; विशेष रूप से। घरेलू मुद्रा <सिक्के

और मुद्रा पैसा है। 2 . ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है

नकद के लिए <मांग जमा धन हैं>। 3. निवेश की गई पूँजी

या एक वस्तु <मुद्रा बाजार> के रूप में कारोबार किया जाता है। 4. निधियाँ; राशि

धन का <निवेश धन>। - (4 अर्थ में) धन भी लिखा जाता है।

विनियम का माध्यम; कानूनी निविदा "देखें।

71. 'लेख' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है।

"आम तौर पर, एक विशेष वस्तु या चीज़ <कपड़ों की वस्तु>।

72. 'बुलियन' शब्द को संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड में परिभाषित किया गया है।

शब्दकोश के रूप में 'सिक्का बनाने से पहले थोक में सोना या चांदी, या वजन से मूल्यवान'

एम. प्रिंसिपल ऑफ एजुसडेम जेनरिस; नॉसिटर ए
एसओसीआईआईएस

73. धारा 69 ए अस्पष्टीकृत धन, सराफा,

आभूषण '। इसके बाद 'या अन्य मूल्यवान लेख' शब्द आते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 'अन्य मूल्यवान लेख' शब्दों को सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए? यह सिद्धांत तब लागू होता है जब निम्नलिखित शर्तें मौजूद होती हैं [न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 14 वां संस्करण]:

" (1) मूर्ति में विशिष्ट शब्दों की गणना होती है; (2)

गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं; (3) कि [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ग या श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है; (4)

सामान्य शब्द गणना का अनुसरण करते हैं; और (5) कोई संकेत नहीं है

एक अलग विधायी इरादे का "। यदि गणना के विषय

एक व्यापक आधारित जीनस के साथ-साथ एक संकीर्ण जीनस से भी संबंधित है, वहाँ

यह कोई सिद्धांत नहीं है कि सामान्य शब्दों को सीमित किया जाना चाहिए संकीर्ण वंश "।

74. अधिनियम की धारा 32 (1) के स्पष्टीकरण 3 (बी) के संदर्भ में, आयकर आयुक्त, कोलकाता बनाम. एसएमआईएफएसराइट्स लिमिटेड "1, निम्नलिखित रूप में आयोजित:

" 8. हम नीचे धारा 32 (1) के स्पष्टीकरण 3 को उद्धृत करते हैं।

अधिनियम:

" स्पष्टीकरण 3. — इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

पद 'परिसंपत्तियाँ' और 'परिसंपत्तियों का खंड' का अर्थ होगा

(क) मूर्त परिसंपत्तियाँ, इमारतें, मशीनरी, संयंत्र या

फर्नीचर;

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या इसी तरह के किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना। "

स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है कि "परिसंपत्ति" पद का अर्थ एक अमूर्त परिसंपत्ति होगा, जिसका ज्ञान होना-कैसे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,

लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार

समान प्रकृति। "कोई अन्य व्यवसाय या" शब्दों को पढ़ना।

स्पष्टीकरण के खंड (बी) में समान प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार

3 यह इंगित करता है कि सद्भावना "किसी भी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगी।

समान प्रकृति का अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार। द.

उक्त अभिव्यक्ति जो स्पष्टीकरण 3 (ख) में स्थान पाती है। 9. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि "सद्भावना" अधिनियम की धारा 32 (1) के स्पष्टीकरण 3 (बी) के तहत एक संपत्ति है।

75. रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम। कलेक्टर

राल् एक्साइज, बड़ौदा 22, न्यायालय एक अपवाद पर विचार कर रहा था।

ई एक छूट अधिसूचना में और की प्रयोज्यता पर विचार किया

तथ्यों के लिए नोसितुर ए सोसाइटी का सिद्धांत: 2) 13 एससीसी 488 + 0) 3 एससीसी 447
1/एस।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 12. वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत जिसके द्वारा एक सामान्य शब्द अपने संदर्भ के कारण सीमित व्याख्या प्राप्त करता है

अच्छी तरह से स्थापित। जिस संदर्भ के साथ हमारा संबंध है, हम वैध रूप से "समाज की उपेक्षा" के सिद्धांत को अपना सकते हैं। इस अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि "किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा आंका जाता है जिसे वह रखती है।" जे. गजेंद्रगडकर ने बॉम्बे राज्य बनाम में शासन के दायरे की व्याख्या की। आतिथ्य मजदूर सभा [(1960) 2 एस. सी. आर. 866: आकाशवाणी 1960 एससी 610: (1960) 1 एल. एल. जे. 251] निम्नलिखित शब्दों में: (एससीआर पीपी। 873-74)

" मैक्सवेल के अनुसार, इस नियम का अर्थ है कि, जब दो या दो से अधिक शब्द जो समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं

एक साथ मिलकर उन्हें उनके संज्ञानात्मक अर्थों में उपयोग किया जाता है। वे एक-दूसरे से अपना रंग लेते हैं, यानी जितना अधिक सामान्य होता है, उतना ही कम सामान्य के समान एक अर्थ तक सीमित होता है। इसी नियम की व्याख्या इस प्रकार "शब्दों और" में की गई है।

वाक्यांश "(खंड। XIV, पी। 207): " संबद्ध शब्द एक दूसरे से अपना अर्थ लेते हैं, जिसका दर्शन यह है कि एक संदिग्ध शब्द का अर्थ शब्दों के अर्थ के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

इसके साथ जुड़े; इस तरह के सिद्धांत की तुलना में व्यापक है

मेक्सिम इजस्टेम जेनरिस "। वास्तव में बाद वाला उक्ति "केवल व्यापक उक्ति नोसिटर ए सोसाइटिस का एक चित्रण या विशिष्ट अनुप्रयोग है"। तर्क यह है कि विशेषताओं की कुछ आवश्यक विशेषताएं हमेशा "व्यापार और व्यापार" शब्दों के साथ जुड़ी होती हैं जैसा कि लोकप्रिय और पारंपरिक अर्थों में समझा जाता है, और यह इन विशेषताओं का रंग है जो परिभाषा में उपयोग किए गए अन्य शब्दों द्वारा लिया जाता है, हालांकि उनका सामान्य महत्व बहुत व्यापक हो सकता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज केवल निर्माण का एक नियम है और यह उन मामलों में प्रबल नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट है कि परिभाषित शब्द के दायरे को तदनुसार व्यापक बनाने के लिए व्यापक शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया गया है। यह केवल वहाँ है जहाँ विधायिका का इरादा संबद्ध करने में है

संकीर्ण महत्व के शब्दों के साथ व्यापक शब्द संदिग्ध हैं, या अन्यथा स्पष्ट नहीं हैं कि निर्माण के वर्तमान नियम को उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है। इसे वहाँ भी लागू किया जा सकता है जहाँ व्यापक महत्व के शब्दों का अर्थ संदिग्ध है; लेकिन, जहाँ व्यापक शब्दों का उपयोग करने में विधायिका का उद्देश्य स्पष्ट और स्पष्ट है।

जा सकता है

अस्पष्टता, विचाराधीन निर्माण के नियम को दबाया नहीं

"[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में कई संदर्भों में लागू किया गया है जहां अदालत अपने दिमाग में स्पष्ट है कि विचाराधीन शब्द का बड़ा अर्थ उस संदर्भ में नहीं किया जा सकता था जिसमें इसका उपयोग किया गया है। मामले बहुत अधिक हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है

यहाँ चर्चा करें। चित्रण के माध्यम से उनमें से एक का उल्लेख करना पर्याप्त होना चाहिए। रेनबो स्टील्स लिमिटेड बनाम। सीएसटी [(1981) 2 एससीसी 141: 1981 एस. सी. सी. (कर) 90] इस न्यायालय को कर लगाने वाले यातायात में प्रविष्टि के संदर्भ में 'पुराने' शब्द का अर्थ समझना था।

जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" पुरानी, बेकार, अनुपयोगी या अप्रचलित मशीनरी, दुकानें

या अपशिष्ट उत्पादों सहित वाहन।

हालांकि शुल्क वस्तु व्यापक शब्द के उपयोग के साथ शुरू हुई

' पुराना ', अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "प्रवेश में होने वाली" पुरानी मशीनरी 'अभिव्यक्ति के भीतर आने के लिए, मशीनरी

पुरानी मशीनरी इस अर्थ में होनी चाहिए कि यह गैर हो गई है

कार्यात्मक या गैर-उपयोग योग्य "। दूसरे शब्दों में, न केवल मशीनरी की आयु, जो व्यापक अर्थों में प्रासंगिक होगी, बल्कि उसके बाद के शब्दों द्वारा इंगित किए गए अनुरूप मशीनरी की स्थिति को इसके उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक माना जाता था।

कानून "।

76.

एक समाज के बारे में और यह इजस्टेम के साथ कैसे तुलना करता है

सामान्य तौर पर, वैधानिक व्याख्या पर जी. पी. सिंह (ऊपर) में निम्नलिखित कथन उपयुक्त है:

" यह एजुस्टेम जेनरिस के नियम से अधिक व्यापक नियम है; बल्कि

बाद वाला नियम केवल पहले वाले का एक अनुप्रयोग है।

एन. अन्य बिटुमेन 'अन्य मूल्यवान' है

लेख '

77. इस न्यायालय ने एजुस्टेम जेनरिस और नोसितुर ए सोसाइटी के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो निस्संदेह निर्माण के नियम हैं।

उत्तरार्द्ध को विश्वासघाती आधार के रूप में वर्णित किया जा रहा है और पूर्व में एक जीनस के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो कानून में सूचीबद्ध श्रेणियों द्वारा समाप्त नहीं होता है। इस न्यायालय ने शब्द, धन,

मूल्यवान सरफा और वस्तु की परिभाषा का भी उल्लेख किया है। न्यायालय भगवानदास में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देता है। नारायणदास (ऊपर) ने कहा कि अचल संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज या सावधि जमा रसीद अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में योग्य नहीं होगी।

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [के. एम. जोसेफ, जे.]

जो कारण दिए गए हैं, वे हमें सही प्रतीत होते हैं। स्वामित्व का दस्तावेज या सावधि जमा रसीद 'वस्तु' नहीं होगी जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सके। एक लेख में एक वस्तु भी शामिल नहीं होगी।

अचल संपत्ति। यह न्यायालय सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कोई वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए। एक मजबूत संकेत है कि एजुस्टेड जेनरिस का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है, चुहरमल (ऊपर) में इस न्यायालय का एक निर्णय है, जहां शामिल लेख घड़ी थे। एजुस्टेड जेनरिस के आधार पर कल्पना के किसी भी विस्तार से घड़ियों को नहीं लाया जा सकता है। वे तथाकथित धन या सर्राफा या आभूषणों से संबंधित नहीं हैं। 'अन्य मूल्यवान' अभिव्यक्ति के संदर्भ में एक घड़ी की पहचान लेख 'यह होगा कि यह विपणन योग्य है और इसका मूल्य है। जब मूल्य की बात आती है, तो यह देखा जाता है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'मूल्यवान' शब्द की परिभाषा में, इसे 'एक अच्छी कीमत के लायक; वित्तीय या बाजार मूल्य' के रूप में परिभाषित किया गया है। 'मूल्यवान' शब्द को फिर से एक विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया है और संक्षिप्त में इसका अर्थ बहुत अधिक धन के लायक है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसलिए, मूल्यवान को ऐसी किसी भी चीज़ के रूप में नहीं समझा जा सकता है जिसका कोई मूल्य हो। धारा 69 ए को लागू करने में कानून देने वाले का इरादा ऐसी आय प्राप्त करना था जो लेखा पुस्तकों में प्रतिबिंबित नहीं हुई है, लेकिन निर्धारिती की है। यह न केवल निर्धारिती का होना चाहिए, बल्कि यह अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी होनी चाहिए। आइए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करें। आइए हम एक निर्धारिती का मामला लेते हैं जो 50 मोबाइल फोन का मालिक पाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का बाजार मूल्य 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये की कीमत वाली ऐसी वस्तुओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये होगा। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां निर्धारिती को 25 अत्यधिक महंगे कैमरों का मालिक पाया जाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि अच्छी कीमत या बहुत अधिक धन होने के बावजूद, वे इसके दायरे से बाहर रहेंगे

धारा 69 का दूसरी ओर, आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जहाँ एक व्यक्ति

उसके पास 500 कोमल नारियल पाए गए हैं। उनका एक मूल्य होगा और यहां तक कि वे विपणन योग्य भी होंगे, लेकिन 500 कोमल नारियल को मूल्यवान वस्तुओं के रूप में वर्णित करना पूरी तरह से अनुचित हो सकता है। यह दोनों के लिए जाता है

विपणन क्षमता, साथ ही यह भी तथ्य कि इसे 'अच्छी' कीमत के लायक नहीं बताया जा सकता है। प्रत्येक मामले का निर्णय तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि बड़ी राशि या अच्छी कीमत वाली वस्तुएं या चल वस्तुएं समझ में आती हैं, लेकिन ऐसी वस्तुएं जो ऐसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होती हैं, उन्हें 'अन्य मूल्यवान वस्तुएं' शब्दों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। 'अन्य मूल्यवान वस्तुओं' की अवधारणा वस्तुओं के बाजार में आने के साथ विकसित हो सकती है, जिन्हें अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करने पर अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में माना जा सकता है।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

78. बिटुमेन को संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में 'प्राकृतिक रूप से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के काले चिपचिपे मिश्रण' के रूप में परिभाषित किया गया है।

पेट्रोलियम आसवन से अवशेष, जिसका उपयोग सड़क की सतह और छत के लिए किया जाता है। बिटुमेन पेट्रोलियम रिफाइनरियों में एक अवशिष्ट उत्पाद प्रतीत होता है और

इसका उपयोग आमतौर पर सड़क निर्माण में किया जाता है जो इस तथ्य से भी संभावित है कि अपीलार्थी को राज्य के सड़क निर्माण विभाग को बिटुमेन देना था। बिटुमेन आम तौर पर थोक में बेचा जाता है। मूल्यांकन आदेश में, अधिकारी रुपये लेने के लिए आगे बढ़े हैं। 4999.58 प्रति मीट्रिक टन जैसा कि बिटुमेन घोटाले पर एजी रिपोर्ट में लिया गया है। इस प्रकार, यह है कि 2094.52 मीट्रिक टन के लिए बिटुमेन की कीमत रु। 1,04,71, 720.30 . इसका मतलब यह होगा कि एक किलोग्राम बिटुमेन की कीमत 1995-1996 (F. Y.) में केवल 5 रुपये होगी।

79. बिटुमेन कम मात्रा में या बड़ी मात्रा में पाया जा सकता है। यदि 'लेख' को 'मूल्यवान' पाया जाना है, तो कम मात्रा में इसका केवल कुछ मूल्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह 'अच्छी कीमत के लायक' होना चाहिए। धारा 69 ए तब आकर्षित होगी। लेकिन अगर इसे 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में मानना है, तो इसके लिए बड़ी मात्रा में स्वामित्व की आवश्यकता होती है, इस अर्थ में कि बड़ी मात्रा में मूल्य को गुणा करने से, एक 'अच्छी कीमत' या 'बड़ी राशि' प्राप्त होती है।

यह मूल्यवान लेख नहीं होगा। इस प्रकार, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि 'बिटुमेन' को 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को बिंदु III और IV पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। अपीलों की अनुमति है। विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाएगा और

यद्यपि विभिन्न आधारों पर, आयुक्त अपील द्वारा उपरोक्त आधार पर किए गए जोड़ को हटाने का आदेश बहाल हो जाएगा।

ऋषिकेश राय, जे।

1. मैंने अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की विद्वतापूर्ण राय का अध्ययन किया है। मैं उनके फैसले से सहमत हूँ कि उद्देश्यों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए का मानना है कि प्रावधान का प्रभाव केवल तभी लागू होगा जब निर्धारित विवादित माल का मालिक हो और दूसरा, किसी भी वस्तु को 'मूल्यवान' माना जाए।

अनुच्छेद 69 ए के तहत, यह आंतरिक रूप से महंगा होना चाहिए, और इसे मूल्यवान नहीं माना जाएगा यदि एक गैर-मूल्यवान और सामान्य का विशाल द्रव्यमान हो।

उच्च मूल्य को आरोपित करने के लिए स्थान लेख को ध्यान में रखा जाता है। मैं अपनी राय को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित तर्क जोड़ना चाहता हूँ।

एम/एस। डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [हृषिकेश रॉय, जे।]

2. इस मामले में दो प्रमुख प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या इसमें निर्धारिती को संबंधित वस्तुओं के लिए 'मालिक' माना जा सकता है, और दूसरा, क्या 'बिटुमेन' को धन, सर्राफा और आभूषणों के साथ 'अन्य मूल्यवान वस्तु' की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की सामान्य योजना में, ई-वाणिज्य जैसे क्षेत्रों को छोड़कर, प्रत्यक्ष कराधान अटूट रूप से स्वामित्व से जुड़ा हुआ है, न कि केवल अंतर्निहित संपत्ति के कब्जे से, जिससे आय का सृजन होता है। अधिनियम की धारा 22, जो घर की संपत्ति से आय के कराधान का प्रावधान करती है, यह प्रावधान करती है कि निर्धारिती ऐसी संपत्ति का मालिक होना चाहिए जिससे आय हो। धारा 45 में पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण करने वाले मालिकों पर पूंजीगत लाभ पर आयकर लगाने का प्रावधान है। ऐसी परिसंपत्तियाँ और वे जो उन्हें वैध लाभ के लिए परिवर्तित करते हैं। इसी तरह,

धारा 69ए साक्ष्य के एक नियम के रूप में प्रदान करता है कि आकलन प्रभाव लागू करने के लिए- निर्धारिती को धन, सर्राफा, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मालिक होना चाहिए, जिन पर वह संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है। धारा 69बी में यह प्रावधान है कि अल्पोक्तियों के मामलों में निर्धारिती को धन, सर्राफा, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मालिक होना चाहिए। इसलिए, विवादित के स्वामित्व का निर्धारण करना

कर देयता अधिरोपित करने के लिए माल एक महत्वपूर्ण कारक है। केवल अधिकार रखने वाला और माल पर कानूनी स्वामित्व या अधिकार के बिना, कोई व्यक्ति धारा 69A. An के दायरे में नहीं आएगा।

फिर भी माना जाने वाला मालिक माना जाएगा यदि कब्जा लगाया जाता है निर्धारिती पर और इससे बेहतर दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति निर्धारिती के दावे का विरोध नहीं कर रहा है। वर्तमान मामले में, निर्धारिती निश्चित रूप से बिटुमेन का मालिक नहीं था-बल्कि वह वाहक था जो प्रेषक से माल की आपूर्ति कर रहा था-तेल विपणन कंपनियाँ प्रेषक को

सड़क निर्माण विभाग। विशेष रूप से, माल की कम डिलीवरी के कारण, निर्धारिती का कब्जा गैरकानूनी था। अपरिहार्य निष्कर्ष

इसलिए यह है कि धारा 69 ए के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती मालिक नहीं है।

4. इस दूसरे प्रश्न को संबोधित करने के लिए कि क्या बिटुमेन धारा 69 ए के तहत एक मूल्यवान वस्तु है, हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार का लेख है।

बिटुमेन। आम तौर पर, बिटुमेन को एक चिपचिपा, काला, अत्यधिक चिपचिपा, तरल या पेट्रोलियम के अर्ध-ठोस रूप और एक कच्चे तेल उप-उत्पाद के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे डामर के रूप में भी जाना जाता है। जब कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है - आंशिक आसवन, i.e. before इसे औद्योगिक रूप से व्यवहार्य तैयार पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, बीच में, कई उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भग्नांश स्तंभ में कच्चे तेल के आसवन की प्रक्रिया में

तरल पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) जैसे शीर्ष आसवन, मिट्टी का तेल, डीजल, जेट ईंधन और पैराफिन जैसे मध्य आसवन प्राप्त किए जाते हैं और निचले स्तंभ में स्नेहक और तेल जैसे आसवन एकत्र किए जाते हैं। स्तंभ के निचले हिस्से में अवशिष्ट स्तर पर, बिटुमेन और डामर आसवन प्रक्रिया की शाखा हैं। बिटुमेन, हाइड्रोकार्बन का अत्यधिक चिपचिपा परिसर ज्यादातर सड़क की सतह, छत और पानी और क्षारीय प्रतिरोधी पेंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सवाल यह है कि क्या कच्चे तेल के शोधन से इस अवशिष्ट शाखा को वर्गीकृत किया जा सकता है

आयकर अधिनियम की धारा 69 ए के संदर्भ में मूल्यवान लेख

यह ध्यान में रखते हुए कि खंड विशेष रूप से तीन वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है अर्थात् धन, आभूषण और सर्राफा। अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए खंड को पूरी तरह से उद्धृत करना प्रासंगिक है। वह इस प्रकार है:

“ 69 ए. अस्पष्टीकृत धन, आदि। जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती किसी धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और ऐसा धन, सर्राफा, आभूषण या मूल्यवान वस्तु लेखा पुस्तकों में, यदि कोई हो, दर्ज नहीं की जाती है,

आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखा जाता है, और निर्धारिती धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के धन और मूल्य को आय माना जा सकता है।

ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती का।

अधिनियम की धारा 69 ए में उल्लिखित "मूल्यवान वस्तु" अभिव्यक्ति. "1 डिवीजन बेंच के अनुसार, धारा 69 ए के प्रयोजनों के लिए, यह प्रासंगिक नहीं होगा कि क्या विचाराधीन वस्तु को आम तौर पर उच्च मूल्य का माना जाता है और यह एक मूल्यवान वस्तु है। यह संभवतः एक सामान्य और सामान्य लेख हो सकता है लेकिन जो प्रासंगिक होगा वह यह है कि मानी गई वस्तु का कुछ मूल्य होता है। यह वस्तु एक साधारण वस्तु हो सकती है या यह एक उच्च कीमत वाली वस्तु हो सकती है। हाईकोर्ट के मुताबिक,

वस्तु की प्रकृति तब तक महत्वहीन है जब तक कि इसका कुछ मूल्य है जिसे केवल मात्रा द्वारा गिना जा सकता है। इस मामले में, निर्धारिती की आय में वृद्धि रुपये से संबंधित है। 1.05 करोड़ों का बिटुमेन। विशेष रूप से,

डी. एन. सिंह बनाम आयकर आयुक्त और अन्न. (2010) 324 आई. टी. आर. 304 एम/एस.

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [हृषिकेश राँय, जे।]

6. इस मोड़ पर, धनुष बनाम सी. आई. टी. 2 मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करना भी प्रासंगिक है। परिहार प्रावधान, अर्थात अधिनियम की धारा 69 बी। हालांकि इससे पहले

निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 69 ए में 'अन्य मूल्यवान लेख' वाक्यांश की व्याख्या के प्रश्न पर, निष्कर्ष, धारा 69 बी पर भी लागू होंगे। यद्यपि धारा 69 ए मूल्यवान वस्तुओं के अस्पष्टीकृत स्वामित्व से संबंधित है, और धारा 69 बी में प्रावधान व्यय के अल्प विवरण के मामलों को शामिल करता है।

मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण पर, दोनों प्रावधान मूल्यवान वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित हैं। वित्त अधिनियम, 1965 (1965 का 10) के आधार पर जोड़ी गई धारा 69 बी इस प्रकार है:

" 69 बी. निवेशों आदि की राशि, जिसका पूरी तरह से लेखा पुस्तकों में खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने निवेश या किसी भी सर्राफा, आभूषण का मालिक पाया जाता है।

या अन्य मूल्यवान वस्तु, और निर्धारण अधिकारी पाता है कि ऐसा निवेश करने या ऐसी सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने में खर्च की गई राशि आय के किसी भी स्रोत के लिए निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में इस संबंध में दर्ज राशि से अधिक है, और निर्धारिती ऐसी अतिरिक्त राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, अतिरिक्त राशि को आय की राशि नहीं माना जा सकता है।

ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती।

7. अब धनुष (उपरोक्त) के तथ्यों पर लौटते हुए, इसके विपरीत, विद्वान खंड पीठ ने कहा कि किराना स्टोर में स्टॉक धारा 69B.The के उद्देश्यों के लिए एक मूल्यवान वस्तु नहीं है, अदालत ने नोट किया कि किराना स्टोर की वस्तुएं उच्च मूल्य वाली मूल्यवान वस्तुएं नहीं हैं और बल्कि सामान्य वस्तुओं की प्रकृति में हैं। उस मामले में अतिरिक्त स्टॉक लगभग रु। 87,000 / - .

8. दो विपरीत विचारों के बीच, की प्रयोज्यता पर

धारा 69 ए/69 बी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर देयता के उद्देश्य से लेख की प्रकृति पर, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने

2 धनुष जनरल स्टोर बनाम आयकर आयुक्त (2011) 339 आईटीआर 651 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनुष (ऊपर) सही दृष्टिकोण का प्रचार करता है। मुझे धारा 69 ए की व्यापक व्याख्या करने और इसके दायरे में किसी भी और प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को शामिल करने का कोई आधार नहीं दिखता है। विशेष रूप से, यह देखा जा सकता है कि-के लेख

मूल्य-एक प्रजाति है जिसमें मूल्यवान वस्तुएं एक प्रजाति हैं यानी उच्च कीमत वाली वस्तुओं का एक उपसमुच्चय। इसे अलग तरह से कहने के लिए, एक मूल्यवान लेख एक मूल्यवान लेख नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, सीमेंट की एक बोरी, चावल की एक बोरी या हीरे के पत्थर का निश्चित रूप से कुछ मूल्य होगा। लेकिन केवल हीरे के पत्थर को एक उच्च मूल्यवान वस्तु माना जा सकता है। सभी विभिन्न वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करने का अर्थ एक ऐसी व्याख्या होगी जो कानून के उद्देश्य और जहां तक धारा 69 ए का संबंध है, विधायिका के इरादे के लिए विदेशी होगी।

9. इस बिंदु पर, परिपत्र का उल्लेख करना भी उपयोगी हो सकता है

1964 का सं. 20-दिनांक 7.7.1964। इस परिपत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री ने धारा 69 ए को शामिल करने का बचाव करते हुए कहा कि 1964 का संशोधन निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को विरासत में मिले सोने या आभूषणों पर कर लगाने के लिए लागू नहीं किया गया है। लेकिन 'बड़े कर निर्धारकों' के लिए प्रावधान अनिवार्य है जो अपने काले धन और बेनामी संपत्ति को सोने के आभूषणों और सोने के बर्तनों में परिवर्तित करते हैं और इसे विरासत होने का दावा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका का यह कभी भी इरादा नहीं था कि किसी भी और प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को धारा 69A.1t के दायरे में लाया जाना चाहिए, केवल उच्च कीमत वाली कीमती वस्तुएं हैं-जो एक प्रीमियम मूल्य की मांग करती हैं और अक्सर उच्च धन वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी अघोषित आय को जमा करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

इसे सोने और सर्राफा में परिवर्तित करना-कि धारा 69 ए डाली गई थी

आय कर अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं को संबोधित करना और कर योग्य बनाना। इसलिए, विधानमंडल का इरादा, संशोधन के माध्यम से-सोना, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं जैसी वस्तुओं को आयकर के दायरे में लाना था, जहां ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व आम तौर पर आयकर से बचने के इरादे से होता है।

10. इसके विपरीत, यदि नाममात्र मूल्य की सभी विभिन्न वस्तुओं को मूल्यवान वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, तो यह एक बेतुकी बात होगी और विधायी इरादे के साथ भी असंगत होगी। किसी वस्तु के उच्च कुल मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने, धीरे-धीरे प्रति इकाई मूल्य की अनदेखी करने का मतलब धारा 69 ए के तहत कम लागत वाली साधारण वस्तुओं को भी मूल्यवान श्रेणी में शामिल करना होगा। यह विधायिका के तर्क की अवहेलना करेगा। इसमें

संदर्भ में, जब एजुस्टेड जेनरिस के सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो धारा 69 ए में पूर्ववर्ती शब्द जैसे कि धन, सर्राफा, आभूषण से पता चलता है कि 'अन्य मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश उन एम/एस का अनुसरण करता है।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [हृषिकेश राँय, जे।]

शब्दों में, केवल उच्च मूल्य की वस्तुओं को शामिल करना उचित होगा। धारा 69 ए के पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित विशिष्ट वस्तुओं की उपेक्षा करके 'अन्य मूल्यवान वस्तु' या 'मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश को पढ़ने का कोई अन्य तरीका गलत होगा और प्रावधान की सरल भाषा के साथ हिंसा करेगा और विधायी इरादे से परे जाएगा।

11. इसके अतिरिक्त, उक्ति 'नोस्किटुर ए सोसाइटिस' अर्थात् (एक शब्द अपने सहयोगियों द्वारा जाना जाता है) भी उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि

अन्य मूल्यवान वस्तुएँ चांदी की छड़, या आभूषण या धन की प्रकृति की वस्तुएँ होनी चाहिए, अर्थात् केवल उच्च मूल्य की वस्तु। यह दिया गया है कि कोई भी कानून संभवतः सभी मूल्यवान वस्तुओं की एक विस्तृत सूची प्रदान नहीं कर सकता है जो

उच्च आय निर्धारिणी को अपनी आय को समायोजित करने में सुविधा प्रदान कर सकता है। खंड में व्यावहारिक रूप से केवल मूल्यवान वस्तुओं की एक सांकेतिक सूची का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन बिटुमेन को शामिल करने के लिए-कच्चे तेल के प्रसंस्करण के दौरान अवशिष्ट ऑफशूट सामग्री, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, विमानन ईंधन आदि जैसे इसके मूल्यवान घटकों को छोड़कर, धारा 69 ए में 'अन्य मूल्यवान वस्तु' अभिव्यक्ति के भीतर, मेरी राय में, बेतुकेपन में परिणाम होगा, जिसे हमें छोड़ने की आवश्यकता है। किराना स्टोर और बिटुमेन से आम जगह की वस्तुएँ धारा 69 ए में उच्च मूल्य की वस्तुओं से आंतरिक रूप से भिन्न हैं और एक व्याख्यात्मक अभ्यास के माध्यम से, हमें उन्हें सोने की छड़ और आभूषण जैसी वस्तुओं के साथ वर्गीकृत नहीं करना चाहिए।

12. इस स्तर पर "एब्सोलूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटोर नॉन इंडिजेट" यानी (एक सरल प्रस्ताव) सिद्धांत का प्रचार करना भी फायदेमंद हो सकता है।

किसी एक्सपोज़र की आवश्यकता नहीं है। उक्ति में कहा गया है कि यदि विधायिका द्वारा नियोजित भाषा पर्याप्त समझ प्रदान करती है, तो अतिरिक्त कुछ भी आवश्यक नहीं है। न्यू शोरोक स्पनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम एन. वी. रावल 3, बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वित्त अधिनियम, 1956 के माध्यम से संशोधन द्वारा शुरू किए गए आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 35 की उप-धारा (10) के निर्माण पर विचार किया। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि

" एक सुरक्षित और अचूक सिद्धांत जो इन मामलों में मार्गदर्शन का है, वह है शब्दों को पढ़ना और यह देखना कि क्या नियम स्पष्ट रूप से कहा गया है। यदि प्रयुक्त भाषा पर्याप्त स्पष्टता और सटीकता के शब्दों में नियम देती है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है

किया जाए "

3 न्यू शोरोक स्पनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम एन. वी. रावल (1959) 37 आईटीआर 41

1 सी. आई. टी. बनाम कस्तूरी 237 आई. टी. आर. 24 (एस. सी.) देखें।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. इसके अलावा, यह सिद्धांत कि एक राजकोषीय क़ानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, अच्छी तरह से तय किया गया है। 1920 के दशक में केप ब्रांडी सिंडिकेट्स के मामले में न्यायमूर्ति रॉलेट के शास्त्रीय शब्द यहां मूल्यवान सहायता के होंगे। न्यायमूर्ति रॉलेट वाक्यांश की व्याख्या करते हुए-पूर्व ब्रिटिश वित्त अधिनियम, 1915-16 के संदर्भ में युद्ध व्यापार वर्ष निम्नानुसार देखे गए:

..... एक कराधान अधिनियम में केवल उस पर ध्यान देना होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इक्विटी नहीं है एक कर के बारे में। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है। केवल निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है

उपयोग की गई भाषा में।

14. न्यायमूर्ति रॉलेट की उपरोक्त राय को पूर्व मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव ने मंजूरी देते हुए, बनारसी देवी बनाम आईटीओ के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखा था। यह सिद्धांत कि कराधान कानूनों के तहत प्रावधानों और छूटों की विधायी इरादे के अनुसार सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए, हम में से एक ने हाल ही में 2022 में ऑगस्टन टेक्सटाइल कलर्स में भी इसे बरकरार रखा था। 15. उपरोक्त चर्चा के बाद, यह कहा जाना चाहिए कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए की व्याख्या करने के उद्देश्यों के लिए

साधारण और शाब्दिक अर्थ को चुना जाना चाहिए क्योंकि क़ानून में शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं। प्रावधान को किसी जोड़ या घटाव की आवश्यकता नहीं है और यह अपने पैरों पर खड़ा है। 'मूल्यवान लेख' वाक्यांश का सीधा सा अर्थ होगा एक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य बहुत अधिक है।

पैसा '। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है, जैसा कि आक्षेपित क्रम में कहा गया है, किसी भी मूल्य की वस्तु को शामिल करना। इसलिए, धारा 69 ए के संदर्भ में, अस्पष्टीकृत मूल्यवान वस्तु उच्च मूल्य की वस्तु होनी चाहिए जो आय को छिपाने के लिए, कर देयता से बचने के लिए खरीदी जाती है। 'मूल्यवान लेख' वाक्यांश के लिए एक व्यापक व्याख्या को अपनाना और इस तरह इसके दायरे में किसी भी मूल्य की किसी भी वस्तु को शामिल करना अनुचित पाया जाता है। यह भी दोहराया जाना चाहिए कि, आम तौर पर, कराधान कानूनों सहित राजकोषीय कानूनों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और कर को सादृश्य, अनुमान या विस्तार के माध्यम से नहीं लगाया जाना चाहिए। विधायिका द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश।

5 कैपी ब्रांडी सिंडिकेट बनाम अंतर्देशीय राजस्व (1921) 1 के. बी. 64 'बनारसी देवी बनाम आई. टी. ओ. (1964) 7 एस. सी. आर. 539-पैराग्राफ 6 देखें। ऑगस्टन टेक्सटाइल कलर्स लिमिटेड बनाम उद्योग निदेशक और ए. एन. आर. (सिविल अपील सं. 2830/2022) न्यायमूर्ति हृषिकेश राय के अनुसार। पैराग्राफ 13 और 14 एम/एस देखें।

डी. एन. सिंह बनाम आय कर, केंद्रीय, पटना और अन्य के आयुक्त [हृषिकेश राँय, जे।]

16. आयकर अधिनियम की धारा 69 ए के उद्देश्य के लिए, यह है -

घोषित किया कि-एक 'वस्तु' को 'मूल्यवान' माना जाएगा यदि संबंधित वस्तु एक उच्च मूल्य वाली वस्तु है जो एक उच्च मूल्य का आदेश देती है। परिणामस्वरूप, एक साधारण 'लेख' को उसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिसमें धारा 69 ए में उल्लिखित सर्राफा, सोना, आभूषण जैसी अन्य उच्च कीमत वाली वस्तुओं का उच्च मूल्य केवल उसकी थोक मात्रा के बल पर मिल की वस्तु को दिया गया है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो यह किसी कम लागत वाली साधारण वस्तु की बड़ी मात्रा का स्वामित्व नहीं है, बल्कि कीमती सोने का स्वामित्व है।

और इसी तरह, जो धारा 69 ए के तहत मानित आय के निहितार्थ को आकर्षित करेगा।

17. इससे पहले, यह उच्च मूल्य, कम भारी वस्तुएं थीं जो विवेकपूर्ण रूप से स्वामित्व में थीं, जिन्होंने कर से बचने में निर्धारिती की सहायता की। 1964 का संशोधन

केवल बिटुमेन के विशाल द्रव्यमान के आधार पर बिटुमेन जैसी एक अन्यथा साधारण और सामान्य जगह की वस्तु को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। खंड के तहत बिटुमेन को 'मूल्यवान वस्तु' के रूप में वर्गीकृत करना एक गलत तरीका होगा। 69 आयकर अधिनियम का ए।

18. उपरोक्त विश्लेषण करते समय, 1976 का गीत "द फर्स्ट हैलो, द लास्ट गुडबाय" ब्रिटिश गायक रोजर व्हिटेकर द्वारा लिखा और गाया गया था।

मेरे दिमाग में हलचल हो रही है। यहाँ का गायक महान मूल्य की चीजों के बारे में गाते हुए गीतात्मक होता है और उपयुक्त रूप से गाता है "। अगर हम सभी के पास अतिरिक्त सोना होता तो सोना कीमती नहीं होता।" गीत के बोल से संकेत लेते हुए, यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि विधायिका ने खंड की शुरुआत करते समय

69 वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 का ए केवल ऐसी कीमती और आकांक्षी वस्तुओं जैसे सर्राफा और आभूषणों से संबंधित था जो छिपी हुई आय का भंडार बनने में सक्षम हैं।

लेकिन वास्तव में "बिटुमेन" जैसे सामान्य सामान के बारे में चिंतित नहीं थे, जो हमारी सड़क की किसी भी सतह पर दूसरी नज़र को आकर्षित नहीं करेगा।

देश।

19. अंत में, यह माना जाता है कि बिटुमेन धारा 69 ए के संदर्भ में एक मूल्यवान वस्तु नहीं है और यहाँ निर्धारिती नहीं था

598 की धारा 69 ए के प्रयोजन के लिए संबंधित बिटुमेन का स्वामी

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

ए आयकर अधिनियम, 1961। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में अतिरिक्त तर्क के साथ, मैं अपने भाई न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ द्वारा दिए गए फैसले से सहमत हूं।

बिभूति भूषण बोस

(सहायक: नेहा शर्मा, एलसीआरए)